



# दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | ಬೆಂಗಳೂರು और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

**5** पिछली सरकारों के 'पाप के गड्ढे' भरे, 'भ्रष्टाचार का कूड़ा' साफ किया : योगी

**6** क्या एआई मानवता के महाविनाश का कारण बनेगी?

**7** फीफा वर्ल्ड कप में शकीरा की धमाकेदार वापसी



## फर्स्ट टेक

**इंडिगो के विमान के भीतर धुआं दिखा, बंगलूरु हवाई अड्डे पर यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया**  
नई दिल्ली/भाषा। बंगलूरु हवाई अड्डे पर मंगलवार शाम इंडिगो के एक विमान के केबिन में धुआं दिखाई देने के बाद उसमें सवार 230 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इंडिगो ने एक बयान में कहा कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और उन्हें टर्मिनल पर ले जाया गया है, जहां विमान कंपनी के दल उनकी देखभाल कर रहे हैं। एयरलाइन ने कहा, 26 मई 2026 को बंगलूरु से चेन्नई जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6ई 6017 जब उड़ान भरने के लिए रनवे की ओर बढ़ रही थी, तभी विमान में धुआं दिखाई दिया। सुरक्षा के महदेनजर यात्रियों को सुरत बाहर निकाला गया और सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि ९321 विमान में 230 से अधिक लोग सवार थे।

## जीट-सोनीपत मार्ग पर चलेगी 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन

नई दिल्ली/भाषा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 कोच वाली डीएमयू ट्रेन को जीट और सोनीपत के बीच 75 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलाने की मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन डीजल या बिजली आधारित कर्षण के बजाय हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करके विद्युत उत्पादन करेगी। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1,200 किलोवाट है और यह डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सोलिंग स्टॉक (डीपीआरएस) तकनीक पर काम करेगी, जिसके तहत विद्युत क्षमता किसी एक लोकोमोटिव में केंद्रित होने के बजाय पूरी ट्रेन में वितरित होती है।

## अरुणाचल प्रदेश में 188 साल बाद 'ब्लूबेरी' की दुर्लभ प्रजाति पुनः खोजी गई

इंदानगर/भाषा। अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले के सुदूरवर्ती विजयनगर जंगलों में अनुसंधानकर्ताओं ने 'ब्लूबेरी' पौधे की एक दुर्लभ एवं लुप्तप्राय जंगली प्रजाति 'वैक्सिनियम पिलिफेरम' को लगभग 188 वर्षों के बाद फिर से खोज निकाला है, जिसे पहली बार 1836 में दर्ज किया गया था। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में इस प्रजाति की पुनः खोज को एक बड़ी वानस्पतिक उपलब्धि और भारत के जैव विविधता अभिलेखों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि 'वैक्सिनियम पिलिफेरम' एरिकेसी परिवार से संबंधित है, जिसमें ब्लूबेरी और क्रेनबेरी शामिल हैं।

## व्यापक सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चतुर्भुज सुरक्षा तंत्र आवश्यक : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

**बीकानेर/भाषा।** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सेना, सीमा क्षेत्र के नागरिक और स्थानीय प्रशासन से मिलकर बना एक 'चतुर्भुज सुरक्षा तंत्र' व्यापक सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा का यह 'चतुर्भुज सुरक्षा तंत्र' यह दर्शाता है कि सीमा सुरक्षा कोई अलग-थलग जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक क्षेत्रीय दायित्व है।



राजस्थान के बीकानेर जिले के सांचू स्थित बीएसएफ चौकी पर जवानों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जब तक सभी चार हितधारक समन्वय में काम नहीं करेंगे, तब तक सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, "जब तक हम यह चतुर्भुज ढांचा नहीं बनाएंगे, तब तक पूरी तरह सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं की जा सकती।"

गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को सीमा पार से आने

वाले खतरों के साथ-साथ उन आंतरिक खतरों के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए, जिन्हें सीमा पार की ताकतों के इशारे पर देश के भीतर सक्रिय तत्व पैदा करते हैं।

शाह ने कहा, "हमें सीमा पार से उत्पन्न हर खतरे पर नजर रखनी होगी। साथ ही हमें उन लोगों पर भी कानून के तहत कार्रवाई करनी होगी जो देश के भीतर रहकर सीमा पार से संचालित होकर आंतरिक खतरे पैदा करते हैं।" उन्होंने कहा कि केवल ऐसा 'चतुर्भुज सुरक्षा तंत्र' ही राष्ट्रीय सुरक्षा की संपूर्ण संरचना की अवधारणा को पूरा कर सकता है।



## क्वाड की नई पहलों में खनिज, नौवहन निगरानी व ऊर्जा पर ध्यान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) ने समूह को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों को कम करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिज ढांचे की घोषणा की और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी और बंदरगाह अवसंरचना को मजबूत करने के लिए मंगलवार को प्रमुख उपायों का अनावरण किया। समूह के अगले शिखर सम्मेलन के समय को लेकर हालांकि अभी स्पष्टता नहीं बन पाई है।

ऊर्जा सुरक्षा पहल को छोड़कर सभी उपायों को व्यापक रूप से चीन के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते दखल का मुकाबला करने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन

## ऊर्जा सुरक्षा पहल को छोड़कर सभी उपायों को व्यापक रूप से चीन के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते दखल का मुकाबला करने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है

क्वाड ने पूर्वी और दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरे में डालने वाले दबाव की निंदा की। इन नए उपायों की घोषणा नई दिल्ली में समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद की गई। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की। इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी शामिल हुए। विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में कहा, हम विधि के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के प्रति

अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र और उससे परे आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नवाचार, उभरती प्रौद्योगिकियों और विश्वसनीय साझेदारियों की अपार क्षमता को पहचानते हैं।

पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर मंत्रियों ने अपतटीय संसाधन विकास में हस्तक्षेप और सैन्य विमानों, तटरक्षक बल और समुद्री मिलिशिया जहाजों द्वारा किए जा रहे खतरनाक युद्धाभ्यास सहित खतरनाक और जबरदस्ती वाली कार्रवाइयों के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की।

## तंबे समय से जनसांख्यिकीय परिवर्तन का सामना कर रहा असम : हिमंत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

**गुवाहाटी/भाषा।** असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि राज्य में तंबे समय से जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने देश भर में इस घटना का अध्ययन करने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति का स्वागत किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घोषणा की कि केंद्र ने 'अवैध प्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों' से भारत भर में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का आकलन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट

## चीन-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों की 'दृढ़तापूर्वक रक्षा' करने पर सहमत हुए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

**इस्लामाबाद/भाषा।** पाकिस्तान-चीन ने साझा भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करते हुए अपने द्विपक्षीय संबंधों की दृढ़तापूर्वक रक्षा करने और उन्हें विकसित करने पर सहमत व्यक्त की। मंगलवार को जारी एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई। यह बयान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की 23 से 26 मई तक चीन की आधिकारिक यात्रा के समापन पर आया, जो उन्होंने प्रधानमंत्री ली किंग के निमंत्रण पर की थी। शरीफ की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग संबंधी कई दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति शी चिनफिंग और प्रधानमंत्री ली किंग ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से अलग-अलग मुलाकात की और दोनों पक्षों ने चीन-पाकिस्तान सर्वकालिक रणनीतिक सहयोग साझेदारी को और गहरा करने तथा पारस्परिक हित के अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर एक नई व्यापक समझ पर सहमत व्यक्त की।

शर्मा ने कहा, "माननीय अमित शाह जी के सक्रिय नेतृत्व में यह समिति देश भर में हो रहे असामान्य जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करेगी और ठोस समाधान प्रस्तुत करेगी। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों की चिंताओं का गंभीरता से समाधान संभव हो सकेगा।" उन्होंने कहा कि असम तंबे समय से जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रहा है।

## बीपी ने अपने चेयरमैन को पद से हटाया

लंदन/एपी। वैश्विक पेट्रोलियम कंपनी बीपी ने "महत्वपूर्ण शासन मामलों, निगरानी और आचरण" से संबंधित गंभीर चिंताओं के कारण अपने चेयरमैन को पद से हटा दिया है। अल्बर्ट मैनिफोल्ड को पिछले साल ही इस पद पर नियुक्त किया गया था और अब उन्हें अचानक पद से हटा दिया गया। बीपी के बोर्ड ने मंगलवार को इयान टायलर को तत्काल प्रभाव से अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया। कंपनी ने कहा कि स्थायी चेयरमैन की तलाश प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

## कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन:

## सिद्धरामय्या देंगे इस्तीफा, डीके शिवकुमार होंगे नए मुख्यमंत्री!

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

■ माना जा रहा है कि सिद्धरामय्या अगले 2 से 3 दिनों के भीतर अपना इस्तीफा सौंप देंगे।



■ डीके शिवकुमार के समर्थक लगातार दावा कर रहे थे कि सरकार गठन के समय आलाकमान ने शिवकुमार से मुख्यमंत्री पद का वादा किया था

आलाकमान ने शिवकुमार से मुख्यमंत्री पद का वादा किया था लेकिन लगभग वर्षभर से बार बार में यह मुद्दा गर्मा रहा था लेकिन कांग्रेस आलाकमान किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। आज हुई 6 घंटे की लंबी मंत्रालय बैठक के बाद, आलाकमान ने इस बदलाव को हरी झंडी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि पूरा आलाकमान अब सत्ता के इस परिवर्तन के पक्ष में है। पार्टी अब आगामी चुनावों को देखते हुए शिवकुमार के संगठनात्मक कोशल का लाभ उठाना चाहती है।

## वया सिद्धरामय्या जाएंगे दिल्ली?

बताया जाता है कि सिद्धरामय्या को राज्य सभा भेजने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने फिलहाल राज्यसभा के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समय मांगा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पार्टी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रमुख चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहती है।

27-05-2026 28-05-2026  
सूर्योदय 6:41 बजे सूर्यास्त 5:52 बजे

BSE 76,009.70 NSE 23,913.70  
(-479.26) (-118.00)

सोना 16,411 रु. चांदी 281,155 रु.  
(24 कैरेट) प्रति ग्राम प्रति किलो

## निशान मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी पत्रिका  
epaper.dakshinbharat.com



केलाश मण्डेला, मो. 9828233434

## असंवेदनशील पुलिस

बुक्का फाड़ पुलिस जब हँसती, दर्द बताओ किसे कहे। अपराधी हो रहे निरंकुश, किन के दम पर लोग रहे। भ्रष्टाचोरो गुण्डों की अब, खुलती हरगिज़ नहीं तहें। हुए निकम्मे नेता अफसर, बोझ दिलों पर रोज सहें।।

## अपना केवाईसी अपडेट रखें ताकि आप बिना किसी रुकावट के बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकें



यदि आपके केवाईसी संबंधी विवरण में कोई बदलाव नहीं हुआ है,

तो आप अपने पुनःकेवाईसी के लिए एक स्व-घोषणा पत्र जमा करें - जिसे आप पत्र/ऑनलाइन बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/एटीएम/बैंक में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर/ईमेल या कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के माध्यम से जमा करवा सकते हैं।

यदि आपके केवाईसी संबंधी विवरण बदल गए हैं,

तो अपडेटेड विवरणों वाले किसी एक दस्तावेज़ की प्रति प्रदान करें: आधार/मनदाता पहचान पत्र/NREGA जॉब कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र।

आप अपनी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर भी अपना केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।



अधिक जानकारी के लिए,  
https://rbikehtah.rbi.org.in/KYC पर जाएं  
आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर:  
99990 41935/99309 91935

जनहित में जारी  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
RESERVE BANK OF INDIA  
www.rbi.org.in

# नायडू और देवेगौड़ा ने मोदी को 'सबसे लोकप्रिय' प्रधानमंत्री बताया, चौहान को 'भूमिपुत्र' बताया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी को भारत का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बताया और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुरस्कृत अपनाने के विमोचन के अवसर पर उनके राजनीतिक सफर की सराहना की। चौहान की पुरस्कृत के विमोचन के अवसर पर नायडू ने केंद्रीय कृषि मंत्री को जमीनी स्तर का नेता बताया जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 17 वर्षों के कार्यकाल के दौरान बेदाग रहें। इस पुरस्कृत में चौहान ने मोदी के साथ अपने लंबे संबंधों का वर्णन किया है। चौहान को कृषि मंत्री नियुक्त करने के मोदी के निर्णय की प्रशंसा करते हुए नायडू ने कहा कि चौहान



में देश के लिए दूरदृष्टि और जुनून है। उन्होंने कहा, "दिलचस्प बात यह है कि शिवराज का मोदी के साथ जुड़ाव उस समय से शुरू हुआ जब वे बीजेवाईएम (भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मोदी राष्ट्रीय प्रभारी थे... वह मंत्रिमंडल

के वरिष्ठ नेता उन्हें खा जाएंगे। उन्होंने कहा, लेकिन यह फैसला सही साबित हुआ, साथ ही यह भी कहा कि चौहान देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक बनकर उभरे। मोदी के बारे में नायडू ने कहा कि उन्होंने एक बार अपने नाम का अर्थ विकासशील भारत का निर्माण बताया था। उन्होंने प्रधानमंत्री को पंच पुरस्कारों को एक ऐसी प्रणाली में बदलने का श्रेय दिया जो अनाम लोगों को मान्यता देने का प्रयास करती है, जिसमें किसान और जमीनी स्तर पर सेवा में लगे आम नागरिक शामिल हैं, न कि केवल डॉक्टर और अभिनेता।

इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा भी उपस्थित थे, जिन्होंने चौहान की किसान-केंद्रित राजनीति, प्रशासनिक शैली और मोदी के साथ उनके लंबे जुड़ाव को रेखांकित किया। नायडू ने कहा कि मंच पर उपस्थित तीनों नेता, गौड़ा,

चौहान और वह स्वयं, किसानों के पुत्र हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि को केवल एक पेशा नहीं बल्कि एक मिशन के रूप में लिया जाना चाहिए। युवा राजनेताओं से चौहान के जीवन और कार्यों का अध्ययन करने का आह्वान करते हुए नायडू ने कहा कि अपनापन का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। अपने संबोधन में गौड़ा ने भी मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि वह एकमात्र नेता हैं जो देश को आगे ले जाने में सक्षम हैं। साथ ही उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास पर सरकार के दृष्टिकोण को भी उजागर किया। गौड़ा ने कहा कि मोदी और चौहान दोनों ही जमीनी स्तर से ऊपर उठे हैं और उन्होंने किसानों और ग्रामीण समुदायों की स्थिति में सुधार के लिए मिलकर काम किया है।

## केंद्र सरकार की प्राथमिकता जनहित नहीं, कॉर्पोरेट हित है : भाकपा

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को

मंगलवार को 'जनविरोधी' कदम करार दिया और आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जनहित के बजाय कॉर्पोरेट हित को प्राथमिकता दे रही है।

भाकपा महासचिव डी राजा ने पोस्ट कर कहा कि पिछले 10 दिनों में इंधन कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई, जिससे जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। राजा ने कहा, 'पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी एक बार फिर मोदी सरकार के जनविरोधी और कॉर्पोरेट हितैशी चरित्र को उजागर करती है।' भाकपा नेता का कहना है कि बढ़ोतरी से परिवहन लागत, खाद्य कीमतें, कृषि व्यय, सार्वजनिक परिवहन किराये और जीवनयापन की कुल लागत में वृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने पश्चिम एशिया में तनाव के लिए मौजूदा मूल्य वृद्धि को जिम्मेदार ठहराने के लिए भी सरकार की आलोचना की और कहा कि संकट को केवल भू-राजनीतिक घटनाक्रम से नहीं जोड़ा जा सकता। राजा ने कहा, 'सरकार अब अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ाने के रूप में पश्चिम एशियाई संघर्ष का नाम ले रही है।' उन्होंने आरोप लगाया कि आर्थिक कुप्रबंधन, कमजोर होता रूपया और बढ़ती आयात निर्भरता ने भी इस स्थिति में योगदान दिया है।



## नासिक में प्याज किसानों, एमवीए नेताओं का खरीद मूल्य के खिलाफ प्रदर्शन, राजमार्ग अवरुद्ध किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

नासिक/भाषा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में मंगलवार को विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) नेताओं के नेतृत्व में कई प्याज किसानों ने सरकारी खरीद मूल्य के विरोध में प्रदर्शन किया और व्यस्त मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया।

पुलिस ने चांदवाड कस्बे में 'कांदा उत्पादक शेतकरी क्रांति महामोर्चा' द्वारा यातायात बाधित किए जाने के बाद हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कुछ आंदोलनकारियों ने राजमार्ग पर फंसे वाहनों के टायरों की कथित तौर पर हवा निकालने की भी कोशिश की। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार, शिवसेना (उदय बालासाहेब ठाकरे) नेता अंबादास

दानवे और कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बैलगाड़ी पर बैदकर रैली का नेतृत्व किया, बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान पवार ने कहा, सरकार ने प्याज के लिए 1,580 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य घोषित किया है। किसान इससे अप्रसन्न हैं। उन्हें प्याज का 24 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव मिलना चाहिए। सरकार हमारे आंदोलन से डरी हुई है। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्री बुधवार को दिल्ली जाएंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी किसानों के बीच 'मेलोडी' टॉफियां भी बांटी गईं। प्रदर्शनकारियों ने कहा, प्रधानमंत्री ने हाल में इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफियां भेद की थीं, जिसके बाद पारले इंडस्ट्रीज के शेयर बढ गए। उन्हें प्याज भी भेंट करनी चाहिए ताकि उसके दाम भी बढ़ें।

## फर्जी 'परिवहन' पोर्टल का मंडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठग को गिरफ्तार किया है जो सरकारी वेबसाइटों जैसी फर्जी वेबसाइट कथित रूप से बनाता था और उनके माध्यम से देश भर के लोगों से ठगी करता था। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इनमें आधिकारिक परिवहन सेवा वेबसाइट से मिलता-जुलता एक फर्जी पोर्टल भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के इटावा निवासी अंशुल यादव नामक आरोपी को वितीय जांच के बाद गिरफ्तार किया गया। उसने कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स (एमसीए) किया हुआ है। मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) रोहित राजबीर सिंह ने एक बयान में कहा, आरोपी ने 'परिवहन.ऑनलाइन' नामक एक फर्जी वेबसाइट तैयार कर उसका संचालन किया, जिसे सरकारी परिवहन सेवा पोर्टलों जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि आम लोगों को भ्रमित कर उनका विश्वास जीता जा सके। उन्होंने कहा कि पोर्टल का कथित तौर पर ऑनलाइन वाहन नंबर प्लेट बुकिंग और अन्य परिवहन संबंधी सेवाएं प्रदान करने के बहाने लोगों को ठगने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

## बैंकों का प्रदर्शन मजबूत, सालाना 15.90 प्रतिशत की वृद्धि: नागराजू

अगरतला/भाषा। वित्त मंत्रालय में वितीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने मंगलवार को कहा कि देश के सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंक सालाना 15.90 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 'बहुत अच्छा' प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'हमारे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक 15.90 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यह भारतीय इतिहास में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। देश भर में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) भी घटकर 0.40 प्रतिशत रह गई हैं, जो पिछले आंकड़ों की तुलना में कम है।' नागराजू ने पूर्वोत्तर राज्य में दो कार्यक्रमों में भाग लिया, जहां 8,000 लाभार्थियों के लिए 604 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए। उन्होंने कहा कि बैंकों के पास अब मजबूत पूंजी आधार है, जबकि कम एनपीए बैंकों की मजबूती के पीछे एक प्रमुख कारण है। सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए लघु एवं मझोले उद्यमों को समर्थन देने के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपये का व्यापार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है।

## आंध्र प्रदेश सरकार ने इबोला को लेकर विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर जांच शुरू की

विजयवाड़ा/भाषा। आंध्र प्रदेश सरकार ने इबोला वायरस को लेकर विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर मंगलवार से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जांच शुरू कर दी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने इस काम के लिए हवाई अड्डे पर एक शिप्टि रखापित किया है जिसमें एक चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी तैनात हैं। अधिकारी ने कहा, 'आज सुबह हमने इबोला को लेकर जांच शुरू की।' उन्होंने यह भी बताया कि विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर सप्ताह में केवल तीन दिन-मंगलवार, बुधवार और शनिवार को सिंगापुर से अंतरराष्ट्रीय उड़ान का आगमन होता है।

## केरल के सामने वित्तीय संकट, अगले महीने लारंगे 'श्वेत पत्र': सतीशन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार जून के पहले सप्ताह में राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में एक श्वेत पत्र लाएगी।

मुख्यमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में अपनी पहली प्रेस वार्ता में सतीशन ने कहा कि राज्य वित्तीय संकट का सामना कर रहा है और केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी किए जाने के कारण आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और केंद्र-राज्य संबंधों और वित्तीय



मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सतीशन ने कहा कि राज्य से जुड़ी परियोजनाओं और विकास गतिविधियों के लिए केंद्र से अधिकतम सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। उनके मुताबिक, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि राज्य के विकास की परियोजनाओं में केंद्र पूरा सहयोग करे। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा, 'केंद्र सरकार ने तेल की कीमतों में चार बार

बढ़ोतरी की है। कुंफि केरल एक उपभोक्ता राज्य है, इसलिए कीमतों में बढ़ोतरी से केरल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।' उनके अनुसार, खाड़ी देशों से भेजा गया धन केरल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और जब से युद्ध शुरू हुआ है, इसने राज्य को प्रभावित किया है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी' के लिए लीक मामले से जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट के संदर्भ में केरल की घिंटाओं से केंद्र सरकार को अवगत करा दिया गया था।

हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सीडीएफ की प्रचंड जीत के बाद सतीशन ने 18 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस चुनाव में यूडीएफ ने 102 सीटें जीती थीं। एनडीएफ और भाजपा ने क्रमशः 35 और 3 सीटें हासिल कीं।

## हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के लिए 750 करोड़ रुपए मंजूर किए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री नयब सिंह सेनी ने पुलिस विभाग के लिए 750 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जो अगले दो वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल में पुलिस विभाग की विस्तृत समीक्षा की और अगले पांच वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए। इसके साथ ही 'विजन 2047' के तहत क्या लक्ष्य होने चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई।

पंचकूला में पुलिस महानिदेशक ने संवाददाताओं से कहा, 'मुख्यमंत्री ने हमें दिशानिर्देश और मार्गदर्शन दिया। 11 मई को उन्होंने पुलिस विभाग की विस्तृत समीक्षा की और हर पलटू पर जानकारी ली।' उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 750 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जो अगले दो वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले पांच से छह वर्षों में स्वीकृत की गई यह सबसे अधिक राशि है जिसे नए थाने,



पुलिस लाइन, पुलिस चौकियां, भवन, कार्यालय और आवास जैसे बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में राज्य में अपराधों की समीक्षा के लिए एक बैठक भी हुई। उन्होंने बताया कि हाल में हुए सभी बड़े अपराधों को सुलझा लिया गया है। सिंघल ने यह भी बताया कि नारनौल में कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख राव नरेंद्र सिंह के घर में घुसने की कोशिश करने वाले चोरों को बाद में पकड़ लिया गया। ज्ञात हो कि कुछ नकाबपोश लोगों ने हाल में नारनौल में राव नरेंद्र सिंह के पेंटक घर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन शोर सुनकर कुछ कर्मचारी जाग गए और पुलिस को सूचित किया जिसके बाद नकाबपोश वहां से भाग गए।

## मुंबई: फिल्मकार जोया अख्तर के प्रोडक्शन हाउस से 66 हार्ड डिस्क चुराने के आरोप में दो गिरफ्तार

मुंबई/भाषा। मुंबई पुलिस ने फिल्मकार जोया अख्तर और शिमा कागती के यहां स्थित प्रोडक्शन हाउस से फिल्मों और वेब सीरीज से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा वाले 66 हार्ड डिस्क चोरी करने के आरोप में एक ऑफिस बॉय समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह चोरी तब सामने आई, जब 'टाइगर बेबी डिजिटल एलएलपी' की कार्यकारी सहायक महजबीन शेख ने जांच में बिना रीलीज हुई विभिन्न फिल्म और वेब सीरीज परियोजनाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण डिजिटल डेटा था, जिसमें रॉ फुटेज, विज्ञापन सामग्री, पोस्ट-प्रोडक्शन बैकअप और अभिलेख शामिल थे।

अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने सांताक्रुज के वकीला निवासी और ऑफिस बॉय मोहम्मद शाहिद अजीम खान (28) पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने 44 साल पुरानी स्टेशनरी की दुकान के कर्मचारी रितेश सुरेश शाह को स्टोरेज उपकरण बेचे थे। सुनिश्चित करेंगे कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए और एक वर्ष के भीतर पूरी हो जाए। पीठ ने कहा, 'राज्य को प्रभावित क्षेत्रों में सीसीटीवी, एकीकृत निगरानी तंत्र, नियंत्रण केंद्र और संबद्ध तकनीकी ढांचा की स्थापना, संचालन के लिए एतकाल और प्रभावी कदम उठाने होंगे।' न्यायालय ने ज्यूट्टी के दौरान वन रक्षकों और अन्य पंक्ति के सुरक्षा कर्मियों पर बढते हमलों का भी उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआरडी), केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से परामर्श करके, मध्यप्रदेश और राजस्थान को सुरक्षा-धौलपुर सीमा के पास जोड़ने वाले पुल पर उच्च-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी निगरानी कैमरे लगाएंगे।

## भारत एआई तैनाती के अगले चरण का नेतृत्व करने को तैयार: माइक्रोसॉफ्ट अधिकारी



दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत अपने विशाल डेटालपर आधार और मजबूत डिजिटल ढांचे के बल पर वैश्विक कृत्रिम मेधा (एआई) क्षेत्र के अगले चरण के विस्तार का नेतृत्व करने के लिए सक्षम स्थिति में है। माइक्रोसॉफ्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह बात कही। इसका एक आधार उद्यमों द्वारा एआई का तेजी से उपयोग किया जाना भी है। माइक्रोसॉफ्ट में कोरएआई के कार्यकारी उपाध्यक्ष जय पारेख ने पोस्ट में कहा कि भारत में डेटालपरस

## ईडी ने पंजाब में रियल एस्टेट 'धोखाधड़ी' मामले में तलाशी अभियान चलाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

चंडीगढ़/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर एक रियल एस्टेट कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि यह तलाशी अभियान ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े घन शोधन मामले की जांच के तहत चलाया गया। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ रॉयल सटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (सीआरसीपीएल), रॉयल एस्टेट ग्रुप (मोहाली के जीएचएल) और प्रयोग कंसल्ट उर्फ रॉकी, नीरज कंसल, वलजीत सिंह, अनुराग गिवा, लियकत अली, सुमित बराल और कुछ अन्य संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के ठिकानों पर तलाशी ली गई।

वैश्विक स्तर पर ओपन सोर्स में दूसरा बड़ा योगदान देने वाले हैं। उन्होंने एआई से जुड़ी परियोजनाओं में 75 लाख से अधिक योगदान दिए हैं। भारत में निर्मित हाइपरस्त्रिच, ईआरपीनेक्स्ट, टूलजेट और ब्रूनो जैसी ओपन-सोर्स परियोजनाओं का उपयोग अब दुनिया भर के डेवलपर कर रहे हैं। पारेख ने कहा, 'एआई का अगला चरण इस बात से तय नहीं होगा कि कौन सबसे अच्छे मॉडल बनाता है, बल्कि इस बात से तय होगा कि कौन उन्हें भरोसे, गति तथा वास्तविक दुनिया पर प्रभाव डालते हुए बड़े पैमाने पर तैनात कर सकता है। भारत इस बदलाव के लिए विशिष्ट रूप से तैयार है।' पारेख ने देश में उद्यमों द्वारा एआई को तेजी से अपनाने पर प्रकाश डालते हुए डेटालयट के 2026 एंटरप्राइज एआई सर्वेक्षण का हवाला दिया। यह सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर एआई की स्वीकार्यता के मामले में भारत को 15 देशों में से पहले स्थान पर रखता है।

## सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन पर रोक के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने खनन माफियाओं को रोकने के संबंध में वन रक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने समेत अन्य कड़े उपाय करने को कहा है। न्यायालय ने इन राज्यों को प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी और पर्यवेक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना और

संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने इन गतिविधियों में शामिल वाहनों और मशीनरी तथा उनसे जुड़े मालिकों और ठेकेदारों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए भी कहा। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में अवैध रूप से खनन की गई रेत के परिवहन के लिए अपंजीकृत और बिना नंबर वाले वाहनों के इस्तेमाल से संबंधित भीड़िया की हालिया खबरों का संज्ञान लिया। पीठ ने मध्यप्रदेश की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की



अगली सुनवाई 29 मई को होगी। पीठ ने राजू से कहा, 'आप यह सही है, तो आपके अधिकारियों ने अदालत में झूठा हलफनामा दाखिल किया है।' अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर तथ्य सही हैं, तो यह 'चौकाने वाला' है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय 'राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और लुप्तप्राय जलीय वन्यजीवों के लिए खतरा' से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है, 5,400 वर्ग किलोमीटर में तीन राज्यों में फैला संरक्षित क्षेत्र है। दुर्लभ घड़ियाल (लंबी शृंखन वाले मगरमच्छ) के अलावा, यह अभयारण्य लाल मुकुट छतरी कछुओं और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन का भी निवास स्थान है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को अवैध रेत खनन के मुद्दे से निपटने के लिए प्रभावी प्रवर्तन, संस्थागत जवाबदेही और निगरानी एवं निवारक उपायों को तत्काल लागू करने के संबंध में कई निर्देश जारी किए। पीठ ने कहा, 'राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने-अपने वन विभागों में क्षेत्रीय स्तर के प्रवर्तन अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाएं, जिसमें वन रक्षकों के खाली पदों और अन्य कर्मियों की भर्ती करना शामिल है...' न्यायालय ने कहा कि ऐसे पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए और वे राज्य यह

सुनिश्चित करेंगे कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए और एक वर्ष के भीतर पूरी हो जाए। पीठ ने कहा, 'राज्य को प्रभावित क्षेत्रों में सीसीटीवी, एकीकृत निगरानी तंत्र, नियंत्रण केंद्र और संबद्ध तकनीकी ढांचा की स्थापना, संचालन के लिए एतकाल और प्रभावी कदम उठाने होंगे।' न्यायालय ने ज्यूट्टी के दौरान वन रक्षकों और अन्य पंक्ति के सुरक्षा कर्मियों पर बढते हमलों का भी उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआरडी), केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति से परामर्श करके, मध्यप्रदेश और राजस्थान को सुरक्षा-धौलपुर सीमा के पास जोड़ने वाले पुल पर उच्च-रिजॉल्यूशन सीसीटीवी निगरानी कैमरे लगाएंगे।

## ईंधन के दाम बढ़ने से जून में पांच प्रतिशत पर पहुंच सकती है खुदरा मुद्रास्फीति : अर्थशास्त्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और सोने-चांदी पर आयात शुल्क में वृद्धि के चलते खुदरा मुद्रास्फीति जून तक बढ़कर करीब पांच प्रतिशत तक जा सकती है। हालांकि, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक व्याज दरों में किसी भी बदलाव से पहले स्थिति का आकलन करने के लिए 'इंतजार और निगरानी' की नीति अपनाएगा। 15 मई से शुरू हुई 11 दिन की अवधि में पेट्रोल की कीमतों में 7.38 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 7.48 रुपये प्रति लीटर

की बढ़ोतरी हो चुकी है। विश्लेषकों के अनुसार, ईंधन की कीमतों में यह वृद्धि परिवहन, भंडारण और आंशिक रूप से बिजली जैसे क्षेत्रों की लागत बढ़ाकर महंगाई पर सीधा असर डालेगी। इसके अलावा, सरकार ने 13 मई को सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। इस तरह कीमती धातुओं के गैर-जरूरी आयात पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। ईंधाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डी.के. श्रीवास्तव ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में औसतन 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से खुदरा मुद्रास्फीति में करीब 0.75 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत



सिद्धरामय्या ने की वेणुगोपाल और सुरजेवाला से मुलाकात

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

नयी दिल्ली। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने मंगलवार को पार्टी के संगठन महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की। यह मुलाकात कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' में हुई। सिद्धरामय्या ने सोमवार को कहा था कि उन्हें कांग्रेस आलाकमान ने 26 मई को दिल्ली में एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि, सिद्धरामय्या ने कहा था कि उन्हें बैठक के एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी दिल्ली में हैं। सिद्धरामय्या और शिवकुमार

की कांग्रेस नेतृत्व के साथ मुलाकात होने की संभावना है। कर्नाटक में 20 मई को कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद से नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलें जारी हैं। पार्टी और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हालांकि कांग्रेस आलाकमान द्वारा सिद्धरामय्या और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच नेतृत्व को लेकर खींचतान को सुलझाने पर चर्चा किये जाने की व्यापक संभावना है, लेकिन कर्नाटक की चार राज्यसभा सीट के आगामी चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है, जिनमें से कांग्रेस तीन सीट जीत सकती है। राज्य में मतदाता सुधियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू किये जाने का

मुद्दा भी बैठक में शामिल हो सकता है। शिवकुमार के समर्थक 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के साथ ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बनने को लेकर हुए कथित समझौते के तहत उनकी (शिवकुमार) पदोन्नति पर जोर दे रहे हैं। सिद्धरामय्या ने कहा है कि वह अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। शिवकुमार ने लगातार यही कहा है कि वह कांग्रेस नेतृत्व के फंसले का पालन करेंगे और मुख्यमंत्री पद पर परिवर्तन के संबंध में परिणाम समय के साथ पता चल जाएगा। मंत्री पद के इच्छुक कांग्रेस विधायकों के एक बड़े वर्ग की ओर से मंत्रिमंडल में फेरबदल की मांग

जोर पकड़ रही है, ताकि मौजूदा कुछ मंत्रियों को हटाकर उनमें से कुछ को मंत्री बनाया जा सके। कुछ इच्छुक विधायक इस संबंध में पार्टी आलाकमान से मिलने दिल्ली पहुंच चुके हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, सिद्धरामय्या मंत्रिमंडल में फेरबदल के पक्षधर हैं, जबकि शिवकुमार चाहते हैं कि पार्टी पहले नेतृत्व परिवर्तन पर निर्णय ले। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अगर कांग्रेस आलाकमान मंत्रिमंडल में फेरबदल को मंजूरी दे देता है, तो यह संकेत होगा कि मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, जिससे शिवकुमार के मुख्यमंत्री पद पर आसिन होने की संभावना समाप्त हो जाएगी।

शहर की एक कंपनी से 89 लाख रुपये का सोना चुराने के आरोप में नौ कर्मचारी गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। शहर में स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत नौ लोगों को इस कंपनी से सोने की छड़ें और आभूषण चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह मामला नागरथपेट में स्थित निजी सोने की कंपनी के मालिक द्वारा 12 मई को हलासुरुक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद सामने आया। शिकायत के अनुसार, कंपनी में पिछले छह महीनों से कार्यरत नौ कर्मचारियों

ने कथित तौर पर 11 मई की रात को कंपनी परिसर से सोने की छड़ें और आभूषण चुरा लिए और फरार हो गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न कोणों से पूछताछ करके पुख्ता जानकारी जुटाई कि नौ मजदूर बेंगलूरु से विशाखापत्तनम होते हुए पश्चिम बंगाल ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर 13 मई को पुलिस ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन के पास से नौ मजदूरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी की गयी सोने की छड़ और आभूषण बरामद किए। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान

आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली, जिसके बाद उन्हें संबंधित न्यायालय में पेश किया गया और जहां से उन्हें दो दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारी ने बताया कि विस्तृत पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने चोरी इसलिए की क्योंकि उन्हें नियमित रूप से वेतन नहीं मिला था और वे आसानी से पैसा कमाना चाहते थे। पुलिस ने कुल 618 ग्राम सोने की छड़ें और 89 लाख रुपये मूल्य के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

कांग्रेस नेतृत्व ने कर्नाटक में राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों पर मंथन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

नयी दिल्ली। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत राज्य के कई नेताओं साथ बैठक की। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में राज्यसभा और विधान परिषद के आगामी चुनावों पर चर्चा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मन्सुखलाल खन्ना ने दोनों चुनावों के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए बैठक बुलाई थी। बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी उपस्थित थे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि पार्टी मुख्यालय 'इंदिरा भवन' हुई बैठक लगभग दो घंटे तक चली। कर्नाटक में खाली हो रही राज्यसभा की चार सीट में से कांग्रेस तीन और भाजपा एक सीट जीतने की स्थिति में है। सूत्रों ने



बताया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राज्यसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की। खन्ना का राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनके कर्नाटक से ही एक बार फिर चुने जाने की संभावना है। पार्टी शिवकुमार के भाई डीके सुरेश तथा पिछड़े वर्ग के किसी नेता या महिला उम्मीदवार को चुननी में उतार सकती है। समझा जाता है कि कांग्रेस नेताओं ने विधान परिषद सीटों के लिए भी पार्टी के उम्मीदवारों पर चर्चा की। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के संख्या बल को देखते हुए विधान परिषद की सात रिक्त सीट में से कांग्रेस को चार सीट मिलने की संभावना है।

कर्नाटक में 20 मई को कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद से नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलें जारी हैं। शिवकुमार के समर्थक 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के साथ ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बनने को लेकर हुए कथित समझौते के तहत उनकी (शिवकुमार) पदोन्नति पर जोर दे रहे हैं। सिद्धरामय्या ने कहा है कि वह अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। शिवकुमार ने लगातार यही कहा है कि वह कांग्रेस नेतृत्व के फंसले का पालन करेंगे और मुख्यमंत्री पद पर परिवर्तन के संबंध में परिणाम समय के साथ पता चल जाएगा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मेकेदाट्ट पर कर्नाटक की डीपीआर खारिज करने का किया आग्रह

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जयशंकर विजय ने जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के राज्य की याचिका पर विचार किए बिना मेकेदाट्ट परियोजना के लिए कर्नाटक के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर मंगलवार को हैरानी जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में यह भी आग्रह किया कि वह संबंधित अधिकारियों को कर्नाटक द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को खारिज करने का निर्देश दें, क्योंकि यह कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के आदेश और उच्चतम न्यायालय के फैसले के विपरीत है। प्रधानमंत्री मोदी को कर्नाटक सरकार को सलाह देनी चाहिए कि वह नदी क्षेत्र के अन्य राज्यों की सहमति के बिना कोई भी नई परियोजना शुरू न करे और उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन न करे। पत्र में विजय ने कहा कि कावेरी नदी पर मेकेदाट्ट जलाशय के भूमि पूजन की घोषणा के कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयानों ने तमिलनाडु के लाखों किसानों में गहरी चिंता पैदा कर दी है।



अभिनेता रणवीर सिंह ने मैसूरु के चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

मैसूरु। अभिनेता रणवीर सिंह ने मंगलवार को यहां चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उन्हें कांता मिमिक्री मामले में मंदिर जाने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह मंदिर चामुंडी पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। उच्च न्यायालय ने पिछले महीने अभिनेता के खिलाफ फिल्म 'कांतारा-1' में देवता के चित्रण की नकल करने से संबंधित मामले में कार्यवाही रद्द कर दी थी। अदालत का यह फैसला अभिनेता द्वारा बिना शर्त माफी

मांगने के बाद आया। अदालत ने रणवीर के वकील द्वारा प्रस्तुत संशोधित हलफनामे को भी स्वीकार कर लिया था और उन्हें अपने आचरण के लिए प्रार्थित करने हेतु चामुंडी देवी के दर्शन करने को कहा था। यह विवाद गोवा में फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह में अभिनेता द्वारा फिल्म 'कांतारा' को लेकर की गई कथित टिप्पणियों से संबंधित है। रणवीर पर एक देवता की नकल करने और उसे 'शैतान' कहने का आरोप है। धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए एक वकील द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर फिल्म 'धुरंधर' के अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

कर्नाटक में 'घृणास्पद भाषण' विधेयक की आवश्यकता नहीं, मौजूदा कानून पर्याप्त : केंद्रीय गृह मंत्रालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। केंद्रीय गृह मंत्रालय का मानना है कि कर्नाटक का घृणास्पद भाषण पर अंकुश लगाने संबंधी विधेयक अभी आवश्यक प्रतीत नहीं होता और मौजूदा कानूनी ढांचा इस मुद्दे को हल करने के लिए पर्याप्त है। मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार को 'कर्नाटक घृणास्पद भाषण एवं घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक, 2025' पर अपने 'केंद्र-राज्य प्रभाग' के रूप से अवात कराया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा विधेयक को मंजूरी देने से इनकार किए जाने के बाद, कर्नाटक सरकार ने फरवरी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति के लिए इसे गृह मंत्रालय को भेजा था। भाजपा और जद (एस) के कड़े विरोध के बावजूद, यह विधेयक पिछले साल 19 दिसंबर को बेलगावी में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। गृह मंत्रालय (केंद्र-राज्य प्रभाग) ने 12 मई को अपने पत्र में कहा, इस मामले की पड़ताल केंद्र-राज्य प्रभाग में की गई है। इस संबंध में यह कहा जाता है कि जिन मुद्दों के समाधान का प्रयास किया जा रहा है, उनके हल के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य प्रचलित कानूनों में पहले से ही पर्याप्त रूप से

प्रारधान शामिल हैं। राज्य स्तर पर अलग से कानून बनाने से कानूनों का दोहराव और एकरूपता की कमी हो सकती है। इसमें कहा गया, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, ऐसा महसूस होता है कि इस स्तर पर प्रस्तावित कानून की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, और मौजूदा कानूनी ढांचा चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त है। केंद्र के पत्र के बाद, कर्नाटक के संसदीय कार्य एवं विधान विभाग ने 20 मई को राज्य के गृह विभाग को उक्त विधेयक पर टिप्पणी या स्पष्टीकरण देने के लिए पत्र लिखा, ताकि यह केंद्रीय गृह मंत्रालय को शीघ्र उत्तर दे सके। इस विधेयक में घृणा अपराध के लिए एक वर्ष की कैद, जो सात वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, तथा 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है। बार-बार अपराध करने पर अधिकतम सात वर्ष की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की बात कही गई है। भाजपा ने इस विधेयक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला और राजनीतिक प्रतिशोध का खतरनाक हथियार करार दिया था। जनवरी में राज्यपाल ने विधेयक को अपनी सहमति दिए बिना वापस भेज दिया था और कहा था कि इसका संविधान द्वारा संरक्षित लोकतांत्रिक संवाद पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

कांग्रेस में सत्ता संघर्ष के कारण कर्नाटक सरकार 'कोमा जैसी स्थिति' में : अशोक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

हासन। कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के आंतरिक नेतृत्व संघर्ष पर निशाना साधते हुए मंगलवार को दावा किया कि इस सत्ता संघर्ष ने सरकार को कोमा की स्थिति में धकेल दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अशोक ने राज्य में प्रशासन के पूरी तरह चरमरा जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का इतना 'कमजोर' है कि वह मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या और उनके उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच जारी सत्ता संघर्ष को सुलझाने में सक्षम नहीं है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब सिद्धरामय्या और शिवकुमार कर्नाटक में नेतृत्व



परिवर्तन की चर्चाओं के बीच कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात के लिए नयी दिल्ली में हैं। अशोक ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा था कि मंत्रियों को हर 15 दिन में एक बार जिलों का दौरा करना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री खुद इसका पालन नहीं कर रहे हैं। कोई भी अपने जिले में जाकर जनता की शिकायतों का समाधान नहीं कर रहा है, सब दिल्ली के दौरे

का कारण बन सकता है, लेकिन प्रशासन के पतन को एक साल हो चुका है। सदन में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसी को नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा या किस पद से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन रहेगा, कौन जाएगा? लोग इस मुद्दे से थक चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का उच्च कमान कमजोर है...वे नेतृत्व में विफल रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन ध्वस्त हो गया है। सत्ता के लिए आंतरिक कलह के बीच जनता को त्यागने का आरोप लगाते हुए अशोक ने कांग्रेस नेताओं से दिल्ली यात्रा में कटौती करके बेंगलूरु लौटने तथा राज्य के मुद्दों से निपटने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता के लिए मौजूदा सरकार प्रभावी रूप से मृत हो चुकी है।

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण**  
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)  
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, झारका, नई दिल्ली-110075

**31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम**  
(संबंधी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/डीडीएचएस\_डीआईवी/पी/सीआईआर/2022/000000103 दिनांक 29 जुलाई, 2022 के अनुसार)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष
		31 मार्च, 2026	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2026
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय*	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (पिछली अवधि, कर, असाधारण एवं अथवा विशिष्ट मदों से पूर्व)	(4,05,020.23)	(4,79,547.43)	(6,97,446.83)
3.	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण एवं अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	(4,11,480.46)	(4,79,921.55)	(7,08,194.32)
4.	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण एवं अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	(4,11,480.46)	(4,79,921.55)	(7,08,194.32)
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय के बाद (कर पश्चात)**	(4,11,480.46)	(4,79,921.55)	(7,08,194.32)
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	11,80,96,529.81	9,64,60,037.06	11,80,96,529.81
7.	संचिक कोष (पुनर्मुल्यांकन संचित कोष को छोड़कर)	(7,50,904.37)	(95,972.28)	(7,50,904.37)
8.	सिक्वोरिटीज प्रीमियम खाता	-	-	-
9.	नेटवर्थ (6-7)**	11,73,45,625.44	9,63,64,064.78	11,73,45,625.44
10.	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	2,02,27,571.73	2,44,60,647.30	2,02,27,571.73
11.	बकाया प्रतिदेय अधिमान्य शेषर्स	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
12.	ऋण इक्विटी अनुपात**	0.17	0.25	0.17
13.	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ ...../- का) (निरंतरता एवं गैर-निरंतरता प्रचालनों हेतु) 1. बेसिक 2. डायल्यूटेड	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
14.	पूंजी विमोचन संचित कोष	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
15.	डिबेंचर विमोचन संचित कोष	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
16.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
17.	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं

\*प्राधिकरण भारत सरकार की ओर से परिसंपत्तियां रखता है। प्राधिकरण के पास परिचालन आय का कोई स्रोत नहीं है, और इसके सभी कार्य पूरी तरह से भारत सरकार से प्राप्त अनुदान पर निर्भर हैं। तदनुसार, लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया कोई भी अधिशेष या घाटा कूल प्रारितियों पर व्यय की अधिकता को दर्शाता है।  
\*\*नेट वर्थ / शेयरधारकों की निधि = पूंजी आधार, उप कर निधि, अतिरिक्त बजटीय समर्थन, इनवीट से आय, टोल प्लाजाओं के खरखार व्यय तथा रिजर्व और अधिशेष / लाभ एवं हानि खाते के बकाया ऋण की कटौती के पश्चात जमा टोल की वापसी के बाद की कुल राशि।  
\*\*\*ऋण इक्विटी अनुपात = बकाया ऋण / शेयरधारकों का निधि।  
क) उपरोक्त विवरण एनओडीआर नियम के परिणाम 52 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दर्ज तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com एवं www.nseindia.com) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट (www.nhai.gov.in) पर उपलब्ध है।  
ख) एनओडीआर नियम के विनियम 52(4) में संबंधित अन्य लाइन मदों के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को उचित उद्घोषणा कर दी गई है तथा जो वेबसाइट (www.bseindia.com एवं www.nseindia.com) पर देखी जा सकती है।

प्राधिकरण के बोर्ड के लिए एवं की ओर से  
दिनांक: 26.05.2026  
स्थान: नई दिल्ली

ह./-  
सदस्य (वित्त)

ह./-  
अध्यक्ष

सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी



## दक्षिण भारत राष्ट्रमत



## हकीमपुर सीमा चौकी पर जमा हुए अवैध बांग्लादेशियों को शीघ्र निर्वासित किया जाए : शुभेंदु

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

**कोलकाता/बाधा।** पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपमंडल में हकीमपुर सीमा चौकी पर बड़ी संख्या में कथित अवैध बांग्लादेशी नागरिक जमा हो गए हैं और उन्होंने अधिकारियों से उनके निर्वासन में तेजी लाने का आग्रह किया।

कल्याणी में नादिया, हुगली और उत्तर 24 परगना जिलों के अधिकारियों की उपस्थिति में हुई एक प्रशासनिक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, अधिकारी ने दावा किया कि सीमा चौकी पर एकत्रित लोग बांग्लादेश लौटने के इच्छुक थे।

अधिकारी ने सीमा चौकी पर जमा भीड़ का जिक्र करते हुए कहा, जल्दी जल्दी भागो नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वहां मौजूद लोगों को जल्द से जल्द उनके देश वापस भेजा जाए। उन्होंने कहा, हम उन्हें जेलों में

## अखिलेश ने भाजपा सरकार पर फायदे के लिए फर्जी मुठभेड़ करने का आरोप लगाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

**लखनऊ/बाधा।** समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ की घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर मंगलवार को गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुठभेड़ के जरिये समर्थकों को खुश कर रही है।

अखिलेश ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को हिंसक और पुलिस अधिकारियों को अपराधी बना रही है और उसने अपने फायदे के लिए फर्जी मुठभेड़ की घटनाओं के जरिये सरकारी स्तर पर एक पूरा आपराधिक तंत्र खड़ा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं देश की संस्कृति, संविधान और स्वस्थ सामाजिक

## ओडिशा: कान्स्टेबल को पीट पीटकर मार डालने के मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

**भुवनेश्वर/बाधा।** ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा ने राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) कान्स्टेबल सोन्य रंजन स्वैन को पीट-पीटकर मार डालने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

बयान के अनुसार, भुवनेश्वर के सत्य नगर निवासी बिनोद कुमार बेहरा (48) को सोमवार रात केंद्रपाड़ा जिले के डूंदपुर से जांच के दौरान जुटाई गई विशेष सुविधा सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने बताया कि बेहरा सात महीने की घटना के बाद से फरार था और जांच में कांस्टेबल पर हमले में उसकी संलिप्तता

खाना खिलाना या उन पर जनता का पैसा बर्बाद करना नहीं चाहते। इससे वास्तव में भारतीयों को, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, नुकसान हो रहा है। कानून तो था, लेकिन कुछ लोगों ने वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल किया। हम वोट बैंक से ऊपर उठकर देश और राज्य के हित में इसे लागू करेंगे।

राज्य सरकार ने सभी जिलों में गिरफ्तार किए गए विदेशियों और रिहा किए गए विदेशी कैदियों को तब तक रखने के लिए निरुद्ध केंद्र स्थापित किए हैं जब तक कि निर्वासन की औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जाती।

हालांकि इसे केंद्रीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक प्रक्रियात्मक अभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह निर्देश अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से एक सरल घुसपैठ-विरोधी ढांचा पेश करने और यह घोषणा करने के कुछ दिनों बाद आया है कि उनकी सरकार ने बांग्लादेशियों की पहचान करने और उन्हें सीमा पार वापस धकेलने के लिए पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो की नीति अपनाई है।

## पिछली सरकारों के 'पाप के गड़ड़े' भरे, 'भ्रष्टाचार का कूड़ा' साफ किया : योगी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

**लखनऊ/बाधा।** उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार को राज्य की पिछली सरकारों के पाप के गड़ड़े को भरने और भ्रष्टाचार के कूड़े को साफ करने में समय लगा।

योगी ने नगर निगमों के महापौरों के अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे करने के मौके पर 413 करोड़ रुपये की 342 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 'स्वच्छ-सुंदर-समर्थ लखनऊ' पुस्तिका का विमोचन भी किया। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक,



योगी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने पहली बार प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महापौर चुने, जिसकी बदौलत इन निकायों में विकास और स्वच्छता के नए प्रतिमान स्थापित किए। उन्होंने कहा, हमें पिछली सरकारों के 'पाप के गड़ड़े' भरने और 'भ्रष्टाचार का कूड़ा' साफ करने में समय लगा। विकास पर खर्च होने वाला पैसा जनता का है। हम केवल उसका

उचित नियोजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी 17 नगर निगमों के महापौर, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों के चेयरमैन तथा लगभग 14,000 पार्षदों को तीन साल का कार्यकाल पूरा करने पर शुभकामनाएं दीं।

योगी ने कहा, स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ को देश में तीसरा स्थान मिला है। हमें शहर को पहले स्थान पर लाना है। यह सिर्फ महापौर, पार्षद या सफाई कर्मचारी की नहीं,

बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। घर का कूड़ा कूड़ेदान में डालें, गीला-सूखा कूड़ा अलग करें और एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा, जहां 30 वर्षों तक कूड़ा फेंका जाता था, वहां अब राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है। वहां डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। लखनऊ में ग्रीन कोरिडोर, मेट्रो और सभी जन-सुविधाएं उपलब्ध हैं। योगी ने कहा कि 2017 से पहले सपा सरकार में गरीबों के लिए मकान स्वीकृत नहीं होते थे। उन्होंने कहा, हमने जाति, क्षेत्र, मत-मजहब देखे बिना गरीब, युवा, महिला और किसान को केंद्र में रखकर काम किया। शहरी-ग्रामीण क्षेत्र में 65 लाख से अधिक गरीबों को आवास दिए।

## असम विधानसभा में महिला आरक्षण का समर्थन करने वाला प्रस्ताव पारित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

**गुवाहाटी/बाधा।** असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। यह आरोप तब लगाया गया जब संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का समर्थन करने वाले सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी पार्टी ने विधानसभा से संक्षिप्त रूप से बहिर्गमन किया।

शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस विधायकों को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश मिले थे कि प्रस्ताव पारित किए जाने के समय वे सदन में उपस्थित न रहें। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तब सपा और राजद जैसे अपने सहयोगियों की महिला विरोधी नीतियों के आगे घुटने टेक दिए, जब उन्होंने संसद में आरक्षण विधेयक को पारित होने से रोक दिया था। महिला



एवं बाल कल्याण मंत्री अजंता नियोग ने सोमवार को प्रस्ताव पेश किया कि 'महिलाओं की शक्ति का सम्मान करने और महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए, परिशीलन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के

लिए एक तिहाई आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए'। जब शर्मा ने प्रस्ताव पेश किया, तो भाजपा विधायक भुवन पेगु द्वारा अपने भाषण में कांग्रेस के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस और राजद के दल के विधायक कुछ देर के लिए सदन से बाहर चले गए। हालांकि, प्रस्ताव पारित शुरू होने से पहले कांग्रेस सदस्य वापस सदन में लौट आए। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में देवी कामाख्या से लेकर अहोम राजकुमारी जांयमोती और स्वतंत्रता सेनानी कनकलता तक, नारी शक्ति को सम्मान देने की एक समृद्ध परंपरा रही है।

## 'बरेका' में नुकड़ नाटक के माध्यम से गूँजा पर्यावरण संरक्षण का संदेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

**बनारस।** रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) में महाप्रबंधक आशुतोष पंत के नेतृत्व में 15 मई से 5 जून तक विश्व पर्यावरण दिवस-2026 अभियान उस्ताह एवं जनभागीदारी के साथ मनाया जा रहा है।

अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, ऊर्जा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास



के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करना है। इसी क्रम में मंगलवार को बरेका स्थित जलालीपीठ मार्केट में 'हम सबकी जिम्मेदारी' विषय पर एक प्रभावशाली एवं जन-जागरूकता से परिपूर्ण नुकड़ नाटक का आयोजन किया गया। बरेका नाटक दल द्वारा प्रस्तुत इस नाटक ने अपनी जीवंत अभिनय शैली, प्रभावशाली संवादों एवं सामाजिक संदेशों के माध्यम से उपस्थित नागरिकों एवं कर्मचारियों को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया। नाटक के माध्यम से कलाकारों ने



पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश देते हुए जल एवं ऊर्जा बचाने, अधिकाधिक वृक्षारोपण करने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने तथा स्वच्छ एवं हरित वातावरण बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया। प्रस्तुति के दौरान दर्शकों ने कलाकारों का उस्ताहवर्धन करते हुए पर्यावरण सुरक्षा के संदेश को सराहा। कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक अधिकारी जितेंद्र अग्रवाल, उपमुख्य यांत्रिक इंजीनियर/पीओएच राजेश कुमार, जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी एवं



स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। नुकड़ नाटक का निर्देशन सुधाकर मनी द्वारा किया गया। नाटक में आलोक कुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह, सुरशील कुमार त्रिपाठी, मुकेश कुमार दुबे, अविनाश कुमार सिंह, शरद कुमार श्रीवास्तव, बहादुर प्रसाद एवं अमिताभ प्रथम कुमार ने अपनी प्रभावशाली एवं आकर्षक प्रस्तुति से कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं हरित भविष्य के निर्माण हेतु सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।



## राजद की पूर्व नेता रितु जायसवाल भाजपा में शामिल

तेजस्वी की कार्यशैली पर नाखुशी जताई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

**पटना/बाधा।** बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के महिला प्रकोष्ठ की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गईं। पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई।

भाजपा में शामिल होने के बाद रितु ने कहा कि वह बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कार्यशैली से नाखुश थीं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। शपथ ग्रहण के दौरान

भाजपा का नाम लेते समय रितु की जुबान लड़खड़ा गई, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें आगे बोलने का संकेत दिया। बाद में स्वागत भाषण के दौरान सरावगी की भी जुबान फिसल गई और उन्होंने गलती से कह दिया कि रितु राजद में शामिल हुई हैं। हालांकि, सरावगी ने तत्काल अपनी बात सुधारते हुए रितु के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की बात कही।

रितु ने कहा कि आने वाले समय में उनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन वह इससे भयभीत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह कभी बागी नहीं रहें, बल्कि परिहार विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें समर्थन दिया था और निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भी उन्हें 65 हजार मत मिले थे।

## नीति में बदलाव से ओडिशा के बिजली क्षेत्र में आ सकता है 30,000 करोड़ रुपए का निवेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

**भुवनेश्वर/बाधा।** ओडिशा में अगले छह से 12 महीनों में बिजली क्षेत्र में 25,000-30,000 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। इसका कारण राज्य ने तापीय बिजली संयंत्रों से रियायती बिजली आवंटन पर केंद्र की नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया है। बिजली उत्पादों के संघ के एक अधिकारी ने यह बात कही।

राज्य सरकार चालू तापीय बिजलीघरों से पांच प्रतिशत क्षमता की आपूर्ति परिवर्तनीय दरों पर अनिवार्य करने जा रही है। यह उसकी पिछली नीति का स्थान लेगी जिसके तहत परियोजना विकसित करने वालों को राज्य की खरीद वित्तुत प्राधिकरण की पांच प्रतिशत आवंटन योजना पर आवंटित करनी होती थी।

उद्योग जगत के अधिकारियों ने कहा कि ओडिशा में प्रचुर कोयला भंडार और बंदरगाह तक पहुंच और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता सहित रणनीतिक लाभ के बावजूद, पिछली नीति ने नए निवेश को हतोत्साहित किया था। बिजली उत्पादों के संघ के महानिदेशक इंद्र केशरी ने कहा कि ओडिशा में वित्तुत क्षेत्र से विकास के लिए सभी अनुकूल कारक मौजूद हैं, लेकिन परिवर्तनीयता लागत पर बिजली के अधिक अनिवार्य आवंटन ने परियोजनाओं की व्यावहारिकता को प्रभावित किया है। राज्य ने 2008-09 में लागू 14 प्रतिशत आवंटन मानदंड को बरकरार रखा था। इसे बाद में स्थानीय कोयला आधारित परियोजनाओं के लिए इसे घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि कई राज्यों ने केंद्रीय वित्तुत प्राधिकरण की पांच प्रतिशत आवंटन योजना को सिफारिश को अपनाया था।

## बकरीद पर न करें प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी: अरशद मदनवी

**नई दिल्ली/बाधा।** जमीयत उलेमा-ए-हिंद (एएम) के प्रमुख मौलाना अरशद मदनवी ने मुस्लिम समुदाय से सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह करते हुए उनसे प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं करने को कहा। जमीयत द्वारा जारी कथित के मुताबिक, मौलाना मदनवी ने मुसलमानों से कुर्बानी की तस्वीरें व वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा नहीं करने और साफ-सफाई सुनिश्चित करने की भी अपील की। मदनवी ने मुसलमानों को संदेश में कहा कि जिस व्यक्ति के लिए कुर्बानी देना अनिवार्य है, उसे इस फर्ज को निभाना चाहिए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुसलमानों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे स्वयं एहतियाती उपाय करें। मदनवी ने कहा, (कुर्बानी की) प्रचार से बचें, खासकर सोशल मीडिया पर कुर्बाना किए गए जानवरों की तस्वीरें साझा नहीं करें। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को कुर्बानी करते समय सरकारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

## टी20 मुंबई लीग से पहले युगांडा के खिलाफ खेल सकते हैं सूर्य

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

**मुंबई/बाधा।** भारत के टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान सूर्यकुमार यादव 30 मई को होने वाले टी20 मैच में युगांडा क्रिकेट टीम के खिलाफ ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई ईस्ट की ओर से मैदान पर उतर सकते हैं। युगांडा की टीम इस समय मुंबई के दौरे पर है जहां यह चार एकदिवसीय और उतने ही टी20 मैच खेलेगी। टी20 प्रारूप के ये मैच टी20 मुंबई लीग की चार अलग-अलग टीम के खिलाफ खेले जा रहे हैं। टी20 मुंबई लीग की शुरुआत एक जून से होगी।

मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) के सचिव उन्मेश खानविलकर ने मंगलवार को यहां क्रिकेट युगांडा के साथ पांच साल के सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर की घोषणा के दौरान पत्रकारों को बताया, 'यह टीम का हिस्सा है इसलिए उनके



खेलने की पूरी संभावना है।' खानविलकर ने कहा, 'यह भारतीय कप्तान हैं और जब भी यह किसी भी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो इससे टीम का मनोबल बढ़ता है। साथ ही यह क्रिकेट का एक बेहतरीन अनुभव भी साबित होगा।' ट्रायम्फ नाइट्स और युगांडा के बीच 30 मई को होने वाला यह मुकाबला यहां बांद्रा कुर्ला परिसर स्थित एमसीए मैदान पर खेले जाने की उम्मीद है। एमसीए के अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने बताया कि क्रिकेट युगांडा के साथ इस सहमति पत्र के अंतर्गत युगांडा के साथ पांच साल के सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर की घोषणा के दौरान पत्रकारों को बताया, 'यह टीम का हिस्सा है इसलिए उनके

## पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप से पूर्व मांडविया ने कहा, ओलंपिक में शामिल करने की कोशिश जारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

**नई दिल्ली/बाधा।** खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि भारत की 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में योगासन को शामिल करने के लिए जोर दिया जाएगा। यह खेल चार से आठ जून तक अहमदाबाद में पहली विश्व चैंपियनशिप के साथ विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है।

इस विश्व चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 529 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे जिनमें से 114 भारतीय योगासन खिलाड़ी भी शामिल हैं। भारतीय टीम का घयन ट्रायल के बाद किया गया था और अभी यह अहमदाबाद के वीर सावरकर खेल मंदिर में ट्रेनिंग



शिविर में हिस्सा ले रही है। मांडविया ने यहां विश्व योगासन चैंपियनशिप की शुरुआत के मौके पर एक कार्यक्रम में कहा, 'योगासन 2036 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में पारंपरिक खेलों में से एक होगा... हम 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दायेदारी कर रहे हैं और जब ऐसा होगा तो हमारा खेल भी उस सूची में होना चाहिए। भारत सरकार और राष्ट्रीय महासंघ (योगासन भारत) दोनों ही यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे

हैं कि उस समय तक योग एक ओलंपिक खेल बन जाए।' खेल मंत्री ने कहा, 'प्रक्रिया यह है कि एक अंतरराष्ट्रीय महासंघ बनने के लिए आपके पास 75 देशों के हस्ताक्षरकर्ता होने चाहिए जिसके बाद किसी खेल को ओलंपिक में शामिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति से अपील की जा सकती है।' विश्व योगासन के उपाध्यक्ष उदित सेठ ने भी इस विचार का समर्थन किया। सेठ ने कहा, 'हमारा लक्ष्य इसे 2032 के ओलंपिक में एक प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल करवाना है और फिर 2036 में इसे पदक स्पर्धा बनाना है, चाहे ये खेल अहमदाबाद में हो या कहीं और।' विश्व चैंपियनशिप के लिए 529 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। इस चैंपियनशिप में छह आयु वर्गों के लिए 12 स्पर्धाएं होंगी जिनमें 10 वर्ष की आयु से लेकर 55 वर्ष तक के पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होंगे। एशियाई क्षेत्र से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगी। विश्व योगासन के महासचिव जयदीप आर्य ने कहा कि प्रतिभागियों की संख्या और भी अधिक हो सकती थी लेकिन खाड़ी क्षेत्र में चल रहे सैन्य संघर्ष के कारण कुछ देशों को अपना नाम वापस लेना पड़ा। आर्य ने कहा कि युद्ध के कारण तीन-चार देशों को अपना नाम वापस लेना पड़ा लेकिन कुल मिलाकर भागीदारी काफी अच्छी है।

## सुविचार

दान करने से धन नहीं घटता, और क्षमा करने से शक्ति नहीं कम होती, बल्कि ये दोनों चीजें मनुष्य को देवता बना देती हैं।

## दक्षिण भारत राष्ट्रमत

## बदलाव के 12 साल, आगे कई चुनौतियां

साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब कई बुद्धिजीवियों ने कहा था कि 'ये भी पांच साल दिल्ली में गुजार कर गुजरात चले जाएंगे।' अब 12 साल बाद वे 'भविष्यवाणियां' अत्यंत हास्यास्पद लगती हैं। मोदी के नेतृत्व में राजग ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। इसकी कल्पना तो विपक्ष ने भी नहीं की होगी। इन 12 सालों में देश ने कई चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया और कई उपलब्धियां हासिल कीं। याद करें, साल 2014 में इंटरनेट की क्या स्थिति थी? आज हर घर में इंटरनेट पहुंच गया है। तब लोग बिजली-पानी के बिल जमा कराने, ट्रेन, बस और सिनेमा के टिकट खरीदने के लिए घंटों कतारों में खड़े रहते थे। इंटरनेट सुलभ और सरता होने, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलने से वे सारी दिक्कतें दूर हो गईं। पहले, पाकिस्तानी आतंकवादी बेखौफ होकर हमले करते थे। वे पीओके से लेकर पूरे पाकिस्तान में जनसभाएं कर भारत के खिलाफ जहर उगलते थे। पाकिस्तानी फौज उनकी हमदर्द बनकर आतंकवादी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त की। उस दौरान लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले लिए गए। अगर नहीं लिए जाते तो करोड़ों लोगों का जीवन घोर संकट में पड़ सकता था।

भारत में इस अवधि में करोड़ों ऐसे लोगों के खाते खुले, जिन्होंने कभी बैंक शाखा तक नहीं देखी थी। करोड़ों घरों में शौचालयों का निर्माण हुआ। इससे महिलाओं को बहुत सुविधा हुई। हालांकि अभी कई चुनौतियां बाकी हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष की स्थिति के बाद भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसमें काफी प्रगति हुई है, लेकिन हमारी जरूरतों के सामने यह अपर्याप्त है। देश को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के विकल्पों पर काम करना होगा। देशवासियों को डिजिटलीकरण का पूरा फायदा मिलना चाहिए। आज भी कई जगह लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये चक्कर अब खत्म होने चाहिए। हर सुविधा ऑनलाइन मिलनी चाहिए। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। यह हमारे देश की प्रगति में बहुत बड़ी रूकावट है। कई दफ्तर तो ऐसे हैं, जहां भ्रष्टाचार को शिष्टाचार समझा जाने लगा है। रिश्ताखोरी का आलम यह है कि कई अधिकारी लाखों से नीचे तो बात ही नहीं करते। उनकी जेबें भरने के लिए आम आदमी चाहे अपना घर बचे या चीजें गिरवी रखे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भ्रष्ट कर्मचारियों की मनमानी बहुत बढ़ गई है। आम आदमी उनके सामने खुद को असहाय महसूस करता है। प्रधानमंत्री मोदी इस ओर जरूर ध्यान दें। देश को बालादेशी घुसपैठियों से मुक्ति मिलनी चाहिए। अब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार है। असम में भी भाजपा ने सत्ता में वापसी की है। केंद्र में पहले से ही राजग की सरकार है। घुसपैठियों को खदेड़ने में कहीं कोई अड़चन नहीं है। उन्हें पकड़ा जाए और बांग्लादेश भेजा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि वे किसी अन्य राज्य में न चले जाएं, जहां वोटबैंक के नाम पर कोई पार्टी उनकी हितैषी बनकर तैयार मिले। डॉलर के मुकाबले रूपए का ज्यादा कमजोर होना अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। स्वदेशी को बढ़ावा देने के साथ तुरंत ऐसे उपाय किए जाएं, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएं। इस मुहिम को राष्ट्रीय आंदोलन की तरह आगे बढ़ाएं।

## ट्वीटर टॉक



राजस्थान में सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट पर 'खेजड़ी' का पेड़ लगाया गया। पिछले 5 सालों में, हमारे सुरक्षा बलों ने 7.5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं, जो पर्यावरण सुरक्षा और संवेदनशीलता के लिए एक मिसाल है।

-अर्जुनराम मेघवाल

भारत की आत्मनिर्भर नई ताकत: राजस्थान में 'रेयर अर्थ मिनेरल्स' का खजाना मिला! राजस्थान के बाड़मेर-बालोतरा इलाके में मिले रेयर अर्थ मिनेरल्स के बड़े भंडार ने भारत के टेक्नोलॉजिकल भविष्य को एक नई दिशा दी है।

-गजेन्द्रसिंह शेखावत



राजस्थान में सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट पर 'खेजड़ी' का पेड़ लगाया गया। पिछले 5 सालों में, हमारे सुरक्षा बलों ने 7.5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए हैं, जो पर्यावरण सुरक्षा और संवेदनशीलता के लिए एक मिसाल है।

-भजनलाल शर्मा

## प्रेरक प्रसंग

## खेल और संस्कृति

वर्ष 1924 के ओलंपिक में विश्व के खिलाड़ी अपने खेलों से दर्शकों को प्रभावित कर रहे थे। मिथिल युगल टेनिस स्पर्धा के लिए भारत की एक खिलाड़ी मैदान में उतरने वाली थीं। निर्धारित समय पर मैच प्रारंभ हुआ। मिथिल युगल के लिए जब भारत की खिलाड़ी टेनिस कोर्ट पर पहुंची तो पूरी दुनिया के दर्शक दांतों तले अंगुली दबा उठे। वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के बड़े पुत्र सर दाराबजी टाटा की पत्नी मेहरबाई टाटा थीं। साड़ी में उनके खेल को देखकर विदेशी मीडिया और दर्शक हैरान थे। साड़ी में भी वे तेज सर्विस और अपनी चपलता से खेल को होशियारी से खेल रही थीं। उन दिनों टेनिस जैसे खेल में भारतीय महिला खिलाड़ी कम थीं। इस खेल में भाग लेकर जहां उन्होंने पारंपरिक रुढ़ि को तोड़ा, वहीं साड़ी में टेनिस खेलकर भारतीय संस्कृति की अनूठी मिसाल प्रस्तुत की। उन्होंने कई टेनिस प्रतियोगिताओं में साड़ी पहनकर ही जीत हासिल की और पूरी दुनिया के सामने यह मिसाल रखी कि आधुनिक खेल खेलने के लिए अपनी जड़ों और पारंपरिक पहनावे को छोड़ना अनिवार्य नहीं है। खेल जगत के अलावा उन्होंने समाज सेवा

## क्या एआई मानवता के महाविनाश का कारण बनेगी?

ललित गर्ग

मो. 9811051133

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं रह गई है, बल्कि यह मानव सभ्यता के भविष्य का निर्णायक मोड़ बनती जा रही है। जिस गति से यह तकनीक विकसित हुई है, उसने दुनिया को आश्चर्यचकित भी किया है और चिंतित भी। अभी तक विज्ञान और तकनीक मनुष्य के हाथों में उपकरण थे, किंतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहली ऐसी शक्ति है जो निर्णय लेने, सीखने, विश्लेषण करने और सृजन करने की क्षमता के साथ स्वयं को निरंतर विकसित कर रही है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख धर्मगुरु, वैज्ञानिक और नीति-निर्माता इसके खतरों को लेकर गंभीर चेतावनियां दे रहे हैं। हाल ही में वर्तमान पोप लियो चौदहवें द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में व्यक्त की गई विंताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि युद्ध को नैतिक नहीं बनाया जा सकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित युद्ध प्रणाली मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। यह चेतावनी केवल धार्मिक दृष्टि नहीं, बल्कि मानवीय अस्तित्व की रक्षा का प्रश्न है। दुनिया को इस गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

पोप ने सामाजिक और वैश्विक मुद्दों पर जारी अपने आधिकारिक संदेश में एआई को मानवता के समक्ष उभरती सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बताया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल तकनीकी परिवर्तन का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह युद्ध, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को प्रभावित करने वाली शक्ति बनती जा रही है। उन्होंने दुनिया को चेताया कि तकनीक का उद्देश्य मनुष्य पर प्रभुत्व स्थापित करना नहीं, बल्कि उसकी सेवा करना होना चाहिए। उनका संदेश मानव-केंद्रित विकास की अवधारणा को बल देता है, जिसमें विज्ञान और तकनीक को नैतिकता, मानवीय गरिमा और करुणा के अधीन रखा जाए। पोप की यह चेतावनी केवल धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि एक वैश्विक मानवीय आह्वान है कि एआई की अंधी दौड़ में मानवता, संवेदना और नैतिकता का क्षरण न होने दिया जाए। आज जब महाशक्तियां एआई के माध्यम से प्रभाव और नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा में लगी हैं, तब पोप का यह संदेश विश्व समुदाय को संयम, उत्तरदायित्व और मानवीय मूल्यों की ओर लौटने का मार्ग दिखाता है।

पोप ने स्पष्ट कहा कि कोई भी एल्गोरिथ्म युद्ध को नैतिक नहीं बना सकता और तकनीक को मानव विवेक का विकल्प नहीं बनने दिया जा सकता। पोप ने सर्व के सामाजिक संस्कारों से जुड़े अपने इस आधिकारिक पत्र में पहली बार



एआई को रोकेना समाधान नहीं है, लेकिन इसे मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन रखना अनिवार्य है। भारत को ऐसी राष्ट्रीय नीति बनानी होगी जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मानव कल्याण, शिक्षा, चिकित्सा और आर्थिक विकास के लिए हो, लेकिन रोजगार संरक्षण, डेटा सुरक्षा, नैतिक मानदंड और युद्ध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही वैश्विक स्तर पर भी एआई के उपयोग हेतु साझा नियम और अंतरराष्ट्रीय संधियां आवश्यक हैं।

एआई को प्रमुख विषय बनाया, जो इस बात का संकेत है कि इसका प्रभाव केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानव जीवन, समाज और वैश्विक व्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से एआई आधारित स्वायत्त हथियार प्रणालियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इस तकनीक को पूर्णतः मानवीय नियंत्रण में नहीं रखा गया तो यह युद्ध, शोषण और दासता के नए रूपों को जन्म दे सकती है। पोप ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को निरस्त्र करने का आह्वान करते हुए उसका आशय तकनीक का विरोध नहीं, बल्कि उसके अनियंत्रित और अमानवीय उपयोग पर रोक लगाना बताया। उनका कहना था कि युद्ध और शांति से जुड़े निर्णय अंततः नैतिकता, करुणा और विवेक पर आधारित होने चाहिए, उन्हें मशीनों के हवाले नहीं किया जा सकता। आज जब अमेरिका, चीन और अन्य महाशक्तियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ में लगी हैं और युद्ध तकनीकों में इसका उपयोग बढ़ रहा है, तब पोप का यह संदेश मानवता के लिए एक नैतिक दिशा-सूचक के रूप में सामने आया है कि तकनीक मनुष्य की सेवा बने, स्वामी नहीं; और विकास का केंद्र मानव गरिमा, संवेदना तथा विश्वशांति ही रहे।

निश्चित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बैंकिंग, व्यापार, प्रशासन और संचार के क्षेत्र में अप्रत्यूष परिवर्तन किए हैं। रोगों के निदान से लेकर वित्तीय प्रबंधन तक और शिक्षा से लेकर अनुसंधान तक, इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। लेकिन हर तकनीकी क्रांति अपने साथ संकट भी लाती है। आज वही

संकट स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ा संकट रोजगार का है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लाखों लोगों के कार्यों को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया है। ग्राहक सेवा, लेखन, अनुवाद, लेखांकन, सूचना प्रबंधन, प्रोग्रामिंग और कार्यालयी कार्यों में मनुष्य की आवश्यकता तेजी से घट रही है। मशीनें हूप कलागत, अधिक गति और निरंतर कार्य क्षमता के कारण मनुष्य का स्थान ले रही हैं। इससे केवल बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक असंतुलन और आर्थिक विषमता भी गहराएगी। जिन देशों और कंपनियों के पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नियंत्रण होगा, आर्थिक शक्ति भी उन्हीं के हाथों में केंद्रित हो जाएगी। इससे विश्व व्यवस्था में असमानता का नया स्वरूप उभरेगा।

इससे भी अधिक गंभीर प्रश्न वैश्विक सुरक्षा का है। आज अमेरिका, चीन और अन्य महाशक्तियां कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ में लगी हुई हैं। यह प्रतिस्पर्धा केवल तकनीकी श्रेष्ठता तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक प्रभुत्व का नया संघर्ष बन चुकी है।

जैसे कभी परमाणु हथियारों और घातक अस्त्र-शस्त्रों के माध्यम से शक्ति संतुलन स्थापित हुआ था, वैसे ही अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य की सामरिक शक्ति बन रही है। स्वायत्त हथियार प्रणाली, बुद्धिमान ज़ेन और बिना मानवीय हस्तक्षेप के निर्णय लेने वाली युद्ध तकनीकें मानवता के लिए भयावह संकेत हैं। यदि युद्ध का निर्णय मशीनों के हाथों में चला गया तो संवेदना, विवेक और नैतिकता समाप्त हो जाएगी। मशीनों के लिए मानव जीवन केवल आंकड़े होंगे। ऐसी

## नजरिया

## सूरज के तीखे होते तेवर और अल-नीनो

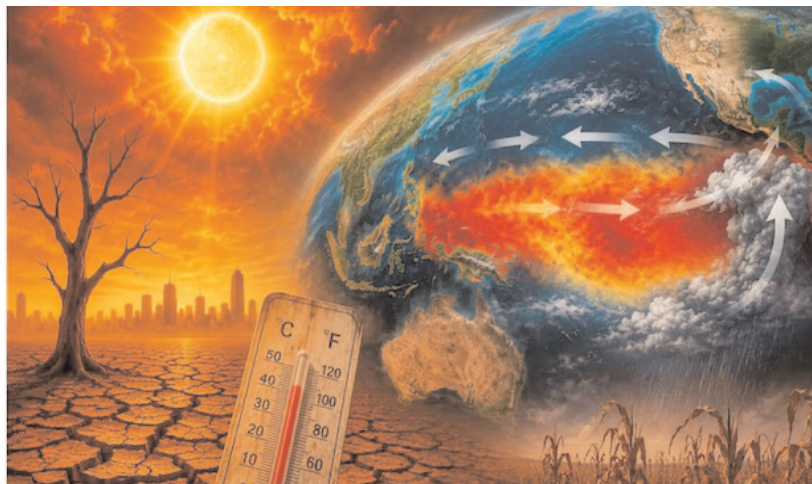
प्रमोद भार्गव

मो. 09425488224

श के ज्यादातर भूभाग पर अंगड़ाई लेता पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस पर कर चुका है। दिल्ली राजधानी क्षेत्र समेत समूचा मध्य व उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। 25 मई को सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश नौतपा शुरू हो जाएं, तब अनुमान है की पहले ही तप रही धरती आसमान से बरसाने वाली इस आग से और अधिक गर्म हो जाएगी। हालांकि भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार धरती का अधिक तपना अच्छी बारिश का संकेत है। मौसम विभाग भी नौतपा में भीषण गर्मी बता रहा है। सनातन पंचांग में उल्लेख मिलता है की इन नौ-दिनों में एक ऐसा समय भी आता है जब सूर्य अपनी सबसे तीव्र ऊर्जा के साथ पृथ्वी पर प्रभाव डालता है। फलतः गर्मी चरम पर पहुंच जाती है।

इस परिदृश्य में वैज्ञानिकों की मानें तो भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में एक ताकतवर महा-अल-नीनो आकर ले रहा है। यह 1877 के बाद सबसे विध्वंसकारी मौसमी आपदा साबित हो सकता है। इसका सीधा असर भारत में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अल-नीनो भारत की जीवन रेखा कहे जाने वाले दक्षिण-पश्चिम मानसून को भी प्रभावित कर सकता है। मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काई मेट के अनुसार इसका मुख्य कारण केवल सामान्य मौसमी बदलाव न होकर ऊष्मा का बन जाने वाला छत्रीनुमा गोला है, जो आधे भारत के राज्यों में मंडरा रहा है। इस समय दिल्ली, उप्र, राजस्थान, हरियाणा, मप्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में गर्मी एकाएक बढ़ गई है। इस प्राकृतिक स्थिति को ऊष्मा का क्षत्रप (हीट डोम) या गुंबद कहा जा रहा है। यह क्षत्रप तब बनता है, जब वायुमंडल में उच्च दबाव की एक प्रणाली लंबे समय तक किसी एक क्षेत्र में ठहर जाती है। इस समय वर्तन के एक ढक्कन की तरह गर्म हवा ऊष्मा को नीचे धरती की तरफ दबाए रखती है, जो तेज गर्मी का कारण बन जाती है। नतीजतन ऐसे क्षेत्रों में तापमान खतरनाक ढंग से बढ़ जाता है और कई दिनों या हफ्तों तक भीषण गर्मी या लू बनी रहती है। गर्मी को इस प्रचंड स्थिति को ग्लोबल वार्मिंग का कारन बताया जा रहा है।

इस बार गर्मी का मिजाज इसलिए भी अलग है, क्योंकि कई तटीय इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में नमी



वाली गर्मी यानी उमस का असर भी देखने में आ रहा है। इससे लू लगने का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। आधे भारत में बढ़ा तापमान लोगों को परत कर रहा है। अतएव हरेक जुवान पर प्रचंड धूप और गर्मी जैसे बोल आमफहम हो गए हैं। हालांकि लू और प्रचंड गर्मी के बीच भी एक अंतर होता है। गर्मी के मौसम में ऐसे क्षेत्र जहां तापमान, औसत तापमान से कहीं ज्यादा हो और पांच दिन तक वही स्थिति यथावत बनी रहे तो इसे 'लू' यानी गर्मी का गोला कहने लगते हैं। मौसम की इस असहनीय विलक्षण दशा में नमी भी समाहित हो जाती है। यही सर्द-गर्म थपड़े लू की पीड़ा और रोग का कारण बन जाते हैं। किसी भी क्षेत्र का औसत तापमान, किस मौसम में कितना होगा, इसकी गणना एवं मूल्यांकन पिछले 30 साल के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। वायुमंडल में गर्म हवाएं आमतौर से क्षेत्र विशेष में अधिक दबाव की वजह से उत्पन्न होती हैं। वैसे तेज गर्मी और लू पर्यावरण और बारिश के लिए अच्छी होती हैं। अच्छा मानसून इन्हीं आकार हवाओं का पर्याय माना जाता है, क्योंकि तपिश और बारिश में गहरा अंतर्संबंध है।

धूप और लू के इस जानलेवा संयोग से कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, तो उसके लू उतारने के इंतजाम भी किए जाते हैं। दरअसल लू सीधे दिमागी गर्मी को बढ़ा देती है। अतएव इसे समय रहते उन्हा नहीं किया तो यह किंगडा अनुपात व्यक्तिको बौरा (पागल) भी सकता है। वैसे शरीर में प्राकृतिक रूप से तापमान को नियंत्रित करने का काम मस्तिष्क में 'हाइपोथैलेमस' अर्थात् 'अधश्चेतक' क्षेत्र करता है।

इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःखायी प्रक्रिया के माध्यम से तापमान को संतुलित बनाए रखना होता है। इसे चिकित्सा शास्त्र की भाषा में हाइपरपीरिक्सिया कहते हैं। यानी शरीर के तापमान में असमान बढ़ रही या अधिकतम बुखार का बढ जाना। इसकी चपेट में बचे और बुजुर्ग आसानी से आ जाते हैं।

हवाएं गर्म या आचारा हो जाने का प्रमुख कारण ऋतुचक्र का उलटफेर और भूतापीकरण (ग्लोबल वार्मिंग) का औसत से ज्यादा बढ़ना है। इसीलिए वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि इस बार प्रलय धरती से नहीं आकाशीय गर्मी से आएगी। जिस आकाश को हम निरीह और खोखला मानते हैं, परंतु वास्तव में यह खोखला है नहीं। भारतीय दर्शन में इसे पांचवां तत्व यूं ही नहीं माना गया है। सचाई है कि यदि परमात्मा ने आकाश तत्व की उत्पत्ति नहीं की होती, तो संभवतः आज हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। हम धांस भी नहीं ले पाते। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों तत्व आकाश से ऊर्जा लेकर ही क्रियाशील रहते हैं। ये सभी तत्व परस्पर परावलंबी हैं। यानी किसी एक तत्व का वजूद क्षीण होगा तो अन्य को भी क्षीण करने की इसी अवस्था से गुजरना होगा। प्रत्येक प्राणी के शरीर में आंतरिक स्फूर्ति एवं प्रसन्नता की अनुभूति आकाश तत्व से ही संभव होती है, इसलिए इसे ब्रह्म तत्व भी कहा गया है। अतएव प्रकृति के संरक्षण के लिए सुख के भौतिकवादी उपकरणों से मुक्ति की जरूरत है। क्योंकि हम देख रहे कि कुछ एकाधिकांश देश भूमंडलीकरण का मुखौटा लगाकर ग्रीन हाउस गैसों

स्थिति महाविनाश की संभावना को जन्म दे सकती है। पोप की यह चेतावनी इसी संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है कि युद्ध का अंतिम निर्णय मानव विवेक के अधीन रहना चाहिए।

साइबर सुरक्षा भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण नई चुनौतियों से घिर गई है। बैंकिंग व्यवस्था, विद्युत तंत्र, रक्षा नेटवर्क और संचार प्रणाली आज डिजिटल माध्यमों पर निर्भर हैं। एआई आधारित साइबर हमले किसी भी राष्ट्र को कुछ घंटों में अस्थिर कर सकते हैं। झूठे संदेश, भ्रामक वीडियो, कृत्रिम चित्र और आवाजों के माध्यम से सामाजिक तनाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। सत्य और असत्य का अंतर मिटने लगा है। यह सूचना तंत्र और लोकतंत्र दोनों के लिए गंभीर संकट है। एआई का एक और विंताजनक पक्ष है-मानवीय नियंत्रण का कमजोर पड़ना। वैज्ञानिक समुदाय का एक वर्ग मानता है कि भविष्य में ऐसी बुद्धिमत्ता विकसित हो सकती है जो मनुष्य की क्षमता से कई गुना आगे निकल जाए। यदि ऐसा हुआ तो नियंत्रण का प्रश्न सबसे बड़ा संकट बनेगा। यह केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व का प्रश्न होगा।

भारत के लिए यह विषय और अधिक महत्वपूर्ण है। भारत युवा शक्ति, विशाल जनसंख्या और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था वाला देश है। यदि एआई को बिना स्पष्ट नीति और नियंत्रण के बढ़ने दिया गया तो रोजगार, शिक्षा और सामाजिक संरचना पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। भारत को विकास और नियंत्रण दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। एआई को रोकेना समाधान नहीं है, लेकिन इसे मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन रखना अनिवार्य है। भारत को ऐसी राष्ट्रीय नीति बनानी होगी जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मानव कल्याण, शिक्षा, चिकित्सा और आर्थिक विकास के लिए हो, लेकिन रोजगार संरक्षण, डेटा सुरक्षा, नैतिक मानदंड और युद्ध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही वैश्विक स्तर पर भी एआई के उपयोग हेतु साझा नियम और अंतरराष्ट्रीय संधियां आवश्यक हैं।

आज सबसे बड़ा प्रश्न तकनीक का नहीं, मानवता का है। क्या मनुष्य अपनी बनाई हुई शक्ति पर नियंत्रण बनाए रख सकेगा? क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जीवन को समृद्ध बनाएगी या उसे नियंत्रित करेगी? क्या विकास संवेदनाओं से बड़ा हो जाएगा? क्या एआई रूढ़ि विस्फोट मानवता के महाविनाश का कारण बनेगी? यही वे प्रश्न हैं जिन पर दुनिया को गंभीर चिंतन करना होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दिशा यदि मानवता केन्द्रित रही तो यह सभ्यता को नई उचाइयों दे सकती है, लेकिन यदि यह शक्ति नियंत्रण और नैतिकता से मुक्त हो गई तो यह मानव इतिहास के सबसे बड़े संकट एवं महाविनाश का कारण भी बन सकती है। इसलिए आज आवश्यकता तकनीकी प्रगति की नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण प्रगति की है-जहां मशीनें विकसित हों, किंतु मानवता सर्वोच्च बनी रहे।





## मारवाड़ी युवा मंच ने होसकेरेहल्ली लेआउट में शुरु की जल एवं स्वच्छता परियोजना

-वॉटरआईडी व कर्नाटक सरकार ने दिया सहयोग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

बंगलूरु। स्थानीय मारवाड़ी युवा मंच (मायुम) बंगलूरु द्वारा वॉटरआईडी एवं कर्नाटक सरकार के सहयोग से होसकेरेहल्ली लेआउट स्थित नोटिफाइड स्लम बोर्ड में जल एवं स्वच्छता परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना का उद्घाटन मायुम के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल, परियोजना संयोजक अशोक अग्रवाल व अन्य सदस्यों की उपस्थिति में हुआ। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्लम बोर्ड में रहने वाले लगभग 270 घरों के 900 निवासियों को स्वच्छ एवं पर्याप्त जल सुविधा उपलब्ध कराना है। इस



परियोजना के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 8 लाख लीटर जल उपभोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। परियोजना के लक्ष्य निवासियों को जल सुविधा, सैनिटरी चैम्बर्स का पुनर्निर्माण, आंगनवाड़ी सैनिटरी क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना है। ममता-महेंद्र अग्रवाल के सौजन्य से शुरु की गई इस पहल में वॉटरआईडी की श्रीमती नंजुजा का सहयोग रहा। मायुम के सचिव सीए विनोद गर्ग ने धन्यवाद दिया।

## शूले संघ ने आचार्यश्री पार्वचन्द्र से शूले से चातुर्मास प्रवेश का निवेदन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

बंगलूरु। जयमल सम्प्रदाय के आचार्यश्री पार्वचंद्रजी व अपुष्पेहा ध्यान प्रणेता, डॉ. पदमचंद्र जी का आगामी चातुर्मास अलसूर में होने जा रहा है। उनके चातुर्मास की तैयारियों जोरों पर चल रही हैं। शूले के श्वेतान्तर स्थानकारी ड्रस्ट संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने शालिनगर जैन स्थानक भवन में विराजित आचार्यश्री के दर्शन किए और उनसे संतो का चातुर्मास प्रवेश

शूले से करने का निवेदन किया। शूले संघ के अध्यक्ष उत्तमचंद्र कोठारी, मंत्री सुनीलकुमार मरलेचा, उपाध्यक्ष मीठालाल दुदेड़िया, कोषाध्यक्ष निहाल कांकरिया, पूर्व अध्यक्ष यशवंतराज सांखला, पूर्व कोषाध्यक्ष इंदरचंद्र भंसाली, निवर्तमान अध्यक्ष देवराज चोपड़ा, पूर्व मंत्री मनोहरलाल बंब, ड्रस्टी महेंद्र कुमार चोपड़ा, संघ सदस्य मोहनलाल चोपड़ा आदि ने संतो से शूले संघ से चातुर्मास प्रवेश के लिए पुनः निवेदन किया तथा आचार्यश्री ने शूले से चातुर्मास प्रवेश की स्वीकृति प्रदान की।



## तपस्या और क्रियाओं से नहीं, वीतराग दशा से मिलेगी वास्तविक मुक्ति : डॉ. समकितमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

बंगलूरु। शहर के मलेश्वरम स्थानक में मंगलवार को आयोजित प्रवचन में डॉ. समकितमुनि ने ज्ञान की सही परिभाषा बताते हुए कहा कि केवल आगम और शास्त्र पढ़ लेने मात्र से कोई 'ज्ञानी' नहीं हो जाता। सच्चा ज्ञानी वह है जिसके भीतर के 'राग-द्वेष' कमजोर पड़ने लगे। जैसे-जैसे राग-द्वेष घटते हैं, वैसे-वैसे इंसान ज्ञानी बनता है और जब यह राग-द्वेष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, तब उसे 'केवल्य ज्ञान' की अवस्था प्राप्त होती है। समाज में संप्रदायवाद और झूठे दावों पर गहरी चोट करते हुए संत प्रवर ने कहा, आजकल अपनी-अपनी परंपरा का रंग रखकर लोग मिथ्या प्रलाप करते हैं। कुछ लोग कहते फिरते हैं कि 'हम तो चौथे आरे के साधक हैं'।

इस पाखंड को तोड़ते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जब वर्तमान में 'वृत्त काल' मौजूद ही नहीं है, तो इस पंचम काल में तुम चौथे आरे की साधना कैसे कर सकते हो? ऐसे मिथ्या भाषण और अपनी परंपरा के अंधे राग में पड़कर कभी किसी का भला नहीं होगा, इससे बचो!

इंद्रभोक्ष का वास्तविक मार्ग बताते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा भ्रम दूर किया। इन्होंने कहा, मुक्ति केवल और केवल उसी की निश्चित है, जिसने अपने भीतर के राग-द्वेष को जीतकर 'वीतराग अवस्था' को पा लिया हो। शुद्ध सामायिक का मर्म समझते हुए मुनिश्री ने कहा कि आज इंसान ने सामायिक को केवल बाहरी वेशभूषा तक सीमित कर दिया है।

याद रखो, सामायिक कभी बाहरी निमित्तों से दूषित या खंडित नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे भीतर के 'दूषित भावों' से टूटती है। यदि तुमने मुँहपती लगा रखी है, लेकिन तुम्हारा मन आत्म-भाव में रमण नहीं कर रहा, तो वह शुद्ध सामायिक नहीं है। और यदि मुँहपती नहीं भी है, लेकिन तुम्हारी आत्मा 'समाधि भाव' में लीन है, तो वह सच्ची सामायिक कहलाती है। कोई भी बाहरी वस्तु और साधन तुम्हारी सामायिक को खंडित नहीं कर सकती। इन्द्र 'बंगलूरु चातुर्मास समिति 2026' की ओर से आगामी 26 जुलाई को महावीर धर्मशाला में होने वाले जीवन संजीवनी चातुर्मास के मंगल प्रवेश एवं भव्य सामूहिक लेले तपस्या' की जानकारी प्रदान की गई। संघ अध्यक्ष प्रकाश बाफना ने सभी को धन्यवाद दिया।



## अनेकांतवाद की नींव पर ही अहिंसा की मंजिल खड़ी करना संभव: राष्ट्रसंतश्री कमलमुनि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

बंगलूरु। शहर के संजयनगर जैन स्थानक में आयोजित प्रवचन सभा में उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रसंतश्री कमलमुनिजी कमलेश ने कहा कि जहां-जहां पर सत्यांश विद्यमान है वह कहीं पर भी हो मेरा है, स्वीकार कर लेना। मेरा ही सत्य है और दूसरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता वह अज्ञानी है। एकांतवाद टकराव और हिंसा का

मार्ग है। अनेकांतवाद की नींव पर ही अहिंसा की मंजिल खड़ी की जा सकती है, एकांतवाद सभी समस्याओं की जननी है, वैचारिक प्रदूषण है। मुनि कमलेशजी ने कहा कि विश्व की संपूर्ण समस्याओं का समाधान अनेकांतवाद के माध्यम से किया जा सकता है। एकांतवाद हटाए और पूर्वाग्रह का प्रतीक है जो समझना भी नहीं चाहता और जो समझना नहीं चाहता वह नादान है।

उन्होंने कहा कि परस्पर विरोधी होने के बावजूद भी अपने-

अपने स्थान पर दोनों सही हो सकते हैं, कार्यशैली अलग हो सकती है परंतु दोनों का लक्ष्य एक ही है।

संतश्री ने कहा कि एकांतवाद पर अड़े रहने वाला ज्ञानी होकर भी अज्ञानी है और समन्वय के मार्ग पर चलने वाला अज्ञानी भी ज्ञानी है। संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता निर्मल मोगरा, निलेश बोहरा, संजय पामेचा, रितेश पामेचा, सुरेश बडोला, रमेश नंदावत, मानक लाल गन्ना, जसवंत गन्ना, मूलचंद्र सहलोत से संतो का स्वागत किया।



## संस्कृति और संस्कार बलि चढ़ रहे कैरियर की धुन में : आचार्यश्री विमलसागरसूरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

गंगावती। स्थानीय मनवांछित पार्श्वनाथ जैन धेतांबर संघ के तत्वावधान में आयोजित यूथ सेमिनार में उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए आचार्यश्री विमलसागरसूरीश्वरजी ने कहा कि आज हजारों प्रतिभाएं अपने घर, परिवार, समाज, संस्कृति और मातृभूमि को छोड़कर दूरदराज के इलाकों में बस रही हैं अथवा विदेश जा रही हैं।

उच्चशिक्षा प्राप्त कर बड़ी उपलब्धियों के सपने साकार करना ही उनका एक मात्र ध्येय है। इन सपनों की सिद्धि में अपनों के संबंध पीछे छूट रहे हैं। अपार धन कमाने और सफल इंसान बनने की चाह में रूने संबंध, सात्विक संवेदनाएं,



कहा कि पढ़ाई और नौकरी के लिए घर से दूर शहरों में बसने या विदेश जाने वाले युवक-युवतियों को यह सावधानी बरतनी अवश्य आवश्यक है कि अपने कैरियर को अच्छा बनाने की धुन में कहीं हम अपनी संस्कृति और संस्कारों की बलि न चढ़ा दें।

आज अधिकांश युवक-युवतियों की जिदगी में यही देखा जा रहा है। यह भारत की उभरती प्रतिभाओं के भविष्य का भयावह दृश्य है। पढ़-लिखकर विद्वान बनने का यह अर्थ कतई नहीं है कि हम अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति, संस्कार और कर्तव्यों को ही भूल जाएं। अगर ऐसा होता है तो यह जीवन की बहुत बड़ी हानि होगी, जिसकी भरपाई अनापसपाप धन की कमाई और किसी भी बड़ी भौतिक सफलता से नहीं की जा सकेगी।



## स्वयं-वी कनेक्ट की बैठक में दिखा महिला उद्यमिता का प्रभाव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

बंगलूरु। शहर के राजाजीनगर स्थित जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जीटी) कार्यालय में स्वयं-वी कनेक्ट-प्रथम महिला व्यापार रेफरल समूह की छठे कार्यकाल की तीसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में शामिल सुखदेवी जैन, रेफरल प्रमुख प्रजा सेठी तथा रेफरल सचिव मोक्ष सोलंकी की उपस्थिति में बैठक हुई। कार्यक्रम में नॉर्थ की महिला अध्यक्ष लक्ष्मी बाफना, संयुक्त

सचिव मीना बडेरा, सचिव रक्षा छाजेड, कोषाध्यक्ष तनुजा मेहता, सुमन रांका एवं उनकी टीम उपस्थिति थी। सभी ने बैठक में सकारात्मकता, प्रेरणा और व्यवसायिक सहयोग की भावना को मजबूत किया। बैठक में इंडियन एंकेडमी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की संस्थापिका शिखा नाग मुख्य वक्ता थी। उन्होंने सार्वजनिक भाषण कला (पब्लिक स्पीकिंग) पर प्रभावशाली सत्र प्रस्तुत करते हुए शारीरिक मुद्रा, आवाज के उतार-चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज और मंच प्रस्तुतियों में महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रभावी

प्रस्तुति के लिए 'डिस्कवर, डिजाइन और डिलीवर' आधारित निस्वर्तीय पद्धति साझा की। कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा 8 मिनट की विशेष व्यावसायिक प्रस्तुति दी गई। केप्टन शुगर की संस्थापिका रक्षा जैन ने अपने ब्रांड और उत्पादों की जानकारी दी। आगंतुकों ने 15 सेकंड की व्यावसायिक प्रस्तुतियां देकर अपने कार्यों का परिचय दिया, जिससे नेटवर्किंग और व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा मिला। बैठक में उलूक प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया।

## बेलगावी में सड़क दुर्घटना में एक परिवार के तीन लोगों की मौत

बेलगावी। कर्नाटक के बेलगावी में मोटरसाइकिल और एक छोटे मालवाहक रिक्शा की टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत पर ही मौत हो गई, जिनमें नौ महीने का एक शिशु भी शामिल है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना सोमवार शाम बेलगावी जिले के रायगांव तालुका में रहते स्टेशन मार्ग के पास हुई। पुलिस ने बताया कि

मृतकों की पहचान रायगांव तालुका के बोम्मनल गांव निवासी महंतेश माने (27), उनकी पत्नी पायल माने (23) और उनके नौ महीने के बेटे समर्थ माने के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि घटना में दंपति की बेटी चैतन्य गंधीरू रूप से घायल हो गई और उसका पास के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

### देवी उत्सव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत



बंगलूरु के बिन्नीपेट में क्षेत्र के नागरिकों द्वारा आयोजित अण्णमा देवी उत्सव कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महेंद्र मुणोत ने देवी मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिया एवं जरूरतमंद बच्चों में शिक्षण सामग्री वितरित की। आयोजकों ने मुणोत को सम्मानित किया।

## कर्नाटक में एलाएलए, एमएलसी के कैबिनेट दर्जे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से न्यायालय का इनकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत  
dakshinbharat.com

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया जिसके तहत विभिन्न बोर्डों और निगमों के प्रमुख के रूप में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों समेत 42 जनप्रतिनिधियों को कैबिनेट दर्जा दिया गया है।

भारत के प्रधान न्यायाधीश सुर्यकांत और न्यायमूर्ति जयपाला याचिका की पीठ से याचिकाकर्ता से उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करने को कहा। पीठ ने कहा, हम इस याचिका का निरस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के परामर्श ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया जितनी गंभीरता से इसे लिया जाना चाहिए था।

शीर्ष अदालत कर्नाटक राज्य

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत सूरी पायला की अपील पर सुनवाई कर रही थी। पायला ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के चार मार्च के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने कहा था, हमें इस तर्क में भी डम लगाता है कि यह याचिका पूरी तरह से जनहित में नहीं है बल्कि याचिकाकर्ता की कुछ प्रयत्नों के लिए आकांक्षाओं के कारण भी दायर की गई है। यह सर्वविदित है कि जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता को मुकदमे में अपने संभावित हित का खुलासा करना अनिवार्य है।

याचिका में दलील दी गई थी कि इन जनप्रतिनिधियों को कैबिनेट दर्जा देने से उन्हें अधिक वेतन, सरकारी वाहन, चालक, ईंधन भत्ता, मकान किराया भत्ता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति जैसे वित्तीय लाभ मिलते हैं। याचिका में कहा गया कि यह लाभ का पद है और संविधान के अनुच्छेद 191 का उल्लंघन करता है जिसके तहत जनप्रतिनिधियों को ऐसे पद धारण करने से अयोग्य ठहराया जाता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि विधानसभा सदस्यों और विधान

परिषद सदस्यों को विभिन्न बोर्डों और निगमों का अध्यक्ष नियुक्त करना अपने-आप में समस्या नहीं होता लेकिन उन्हें कैबिनेट दर्जा देना संविधान के अनुच्छेद 164(1ए) का उल्लंघन है, जो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है। ताकि सरकार का अनावश्यक विस्तार रोका जा सके। याचिका में कहा गया कि 26 जनवरी, 2025 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर 34 जनप्रतिनिधियों को कैबिनेट दर्जा दिया था, जबकि आठ जनप्रतिनिधियों को पहले से यह दर्जा प्राप्त था। इससे एक ही सरकारी अधिसूचना के जरिए इतनी बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों को कैबिनेट स्तर के पद दिए जाने को लेकर चिंता पैदा हुई।

याचिका में कैबिनेट दर्जा वाली नियुक्तियों को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये संविधान के अनुच्छेद 102, 191 और 164 के साथ-साथ कर्नाटक विधानमंडल (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1956 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 का उल्लंघन करती हैं।



पश्चिम बंगाल में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की एक बड़ी भीड़ मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट सब-डिवीजन स्थित हकीमपुर बॉर्डर क्रॉसिंग पर बांग्लादेश वापस लौटने के लिए इकट्ठा हुई।